दैनिक

छत्तीसगढ़ गौरव

डाक पंजीयन क्रमांक :जी2-112/सी.जी/बी.एल.पी./032/ 2023-2026

website:- chhattisgarhgaurav.in

इंदौर स्वीट्स

नमकीन और मिठाईयों की लंबी श्रृंखला के बाद अब केशर कुल्फी और दही कचौड़ी

हमारा विश्वास हैं

एक बार खायेगें, बार-बार आयेगें...

पावर हाऊस रोड, कोरबा

फोन-222833,222733

वर्ष 25 अंक 207 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रूपये | शनिवार 01 नवंबर 2025 | डाक-रविवार 02 नवंबर 2025 | chhattisgarhgaurav@rediffmail.com

नियमों के पालन पर अडिग बालको, आवास खाली पर अब कोई समझौता नहीं

बालको सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के आरोप को मैत्री संघ ने बताया भ्रामक

कोरबा (छ.ग.गौरव) । बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ ने हाल ही में नवनिर्मित बालको सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन (बीएसकेएस) द्वारा 29 अक्टूबर को लगाए गए जबरदस्ती क्वार्टर खाली कराने के आरोपों को पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और गलत बताया है। संघ ने कहा कि बालको प्रबंधन सदैव अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त साथियों के प्रति सम्मानजनक और मानवीय दृष्टिकोण रखता आया है। संगठन ने सभी से कंपनी के नियमों और अनुशासन का सम्मान करते हुए सहयोग बनाए रखने की अपील की, ताकि परिसर में बालको की परंपरा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहें।

जानकारी के अनुसार जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर बालको प्रबंधन ने स्वयं 31 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई को स्थगित रखा और सभी सुविधाएँ यथावत बनाए रखीं। कंपनी का उद्देश्य किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को परेशान करना नहीं है, बल्कि कंपनी की संपत्तियों (क्वार्टर/आवासों) का नियमानुसार पुन: अधिग्रहण करना है, ताकि उन्हें वर्तमान पात्र कर्मचारियों को आवंटित किया जा सके। बालको सेवानिवृत्त मैत्री संघ के संयोजक जेके तिवारी ने बीएसकेएस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि आवास बालको कर्मचारियों के लिए ही हैं। कंपनी के नियमानुसार कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के उपरांत तय समयावधि में आवास खाली कर देना चाहिए। बालको अपने सभी पूर्व और वर्तमान साथियों को परिवार का अभिन्न हिस्सा मानती है और उनके कल्याण एवं गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और नागरिकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि में भाग न लें।

जनप्रतिनिधियों को दिया गया समय हुआ समाप्त

बीतों दिनों टाउनशिप प्रबंधन ने पूर्व में सभी जनप्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। बैठक के दौरान प्रबंधन ने सुझावों का सम्मान करते हुए यह आश्वासन दिया कि 31 अक्टूबर यानि 45 दिन की अवधि तक किसी भी पूर्व कर्मचारी को मकान से नहीं हटाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने यह भी सहमति दी थी कि इस अवधि में आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी की जाए तथा 1 नवंबर से कंपनी नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।

पीएफ और अन्य सुविधाएँ रोकने का आरोप निराधार

जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रावधानों के तहत भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड का एक अपना ट्रस्ट है। प्रावधान के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वेच्छानुसार तीन वर्ष तक अपने पीएफ राशि पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन वैधानिक अनुपालन है जिसे रोका नहीं जा सकता है।

कंपनी के नियमानुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तीन महीने तक आवासीय परिसर में रहने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान कुछ भुगतान अस्थायी रूप से रोके जाते हैं, जो आवास खाली करने के उपरांत पूर्ण रूप से दे दिए जाते हैं। कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बालको अस्पताल में सभी चिकित्सा सुविधाएँ यथावत जारी रखती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी 10 से 15 सालों तक बिजली, पानी, आवास एवं अन्य सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मनमानी का हाल ये है कि ना तो आवास खाली और ना ही रूकी भुगतान राशि जमा कर रहे हैं। बालको कंपनी समय-समय पर उन्हें नोटिस के माध्यम से अवगत कराता रहा है। कंपनी के नियमानुसार किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी की चिकित्सा सुविधा या लंबित भुगतान के विषय में यदि कोई वास्तविक समस्या है, तो वह व्यक्तिगत रूप से नगर प्रशासन विभाग से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकता है।

प्रभावित हो रहे मौजूदा कर्मचारी

अवैध रूप से रह रहे निवासियों के कारण केवल मौजूदा कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि कॉलोनियों की सुरक्षा और व्यवस्था भी खतरे में पड़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र का सही संचालन और सुरक्षित कॉलोनियों का निर्माण केवल उद्योग के हित में नहीं है। यह स्थानीय समुदाय, शहर की संरचना और रोजगार सृजन में भी योगदान देता है।

लैंगिक उत्पीड़न आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक साकेत में सम्पन्न

कोरबा 31 अक्टूबर । नगर पालिक निगम कोरबा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु गठित आंतरिक शिकायत परिवाद समिति की बैठक आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, समिति के समक्ष किसी भी प्रकार की शिकायत व परिवाद न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। निगम में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिरोध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगम में आंतरिक शिकायत/परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी समय-समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत में समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक के दौरान पाया गया कि समिति के पास इस संबंध में केई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार का परिवाद लंबित है, इस पर समिति के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा कार्यालय में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विषयों पर सजग रहने व किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित संज्ञान लेने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में समिति की अध्यक्ष गुलिस्ता साहू, सदस्य सचिव सुभाषिनी आशावान, तारा भगत, कीर्ति अनंत, तिरिथबाई, विनीता सिंह, तुलसीबाई, शिवकुमारी यादव, मालती सोनी, पुष्पा बंजारे, शांतिबाई, रामबाई, तिलका बाई ध्रुव, शीतला गोंड़, ललिता टंडन आदि उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में लिया गया राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ

कोरबा (छ.ग.गौरव) । कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन. केशरी के द्वारा कार्यालयीन सभाकक्ष में आज भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखण्डता और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने का शपथ दिलाया गया।

उन्होंने बताया कि सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महान व्यक्तित्व वाले सरदार बल्लभ भाई पटेल को समर्पित है जिसने बिखरे रियासतों के भारत को एक सूत्र में पिरोया। वे भारत के लौह पुरूष के रूप में उस एकता के प्रतीक बने जिसने आधुनिक भारत की नीव रखी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम सभी को राष्ट्र की एकता को मजबूत करने और देश के नागरिकों के बीच एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहना चाहिए।

असामयिक मृत्यु के दो प्रकरण में आठ लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत

कोरबा (छ.ग.गौरव) । अपर कलेक्टर कटघोरा द्वारा नदी में डूबने एवं सर्पदंश से मृत्यु कुल दो प्रकरण में पीड़ित परिजनों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये के मान से कुल आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जारी आदेश के अनुसार जिले की तहसील पोंड़ीउपरोड़ा के ग्राम केंदई के सूरज धनुहार पिता पंचलाल धनुहार की 01 अगस्त 2025 को हसदेव नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पिता झीटकू राम को चार लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह ग्राम कोईलारगडरा (घुंचापुर) की कौशिल्या पति संतोष धनुहार की गत 24 जुलाई 24 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण उनके पति संतोष धनुहार को चार लाख रूपये की आर्थिक अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

लगातार: मालवाहकों में तब्दील यात्री बसें, न फायर फाइटिंग यंत्र, न ही सुरक्षा के इंतजाम

पहियों तले रौंद रहे सुरक्षा के नियम, आरटीओ खामोश

कोरबा (छ.ग.गौरव) । जिले में यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर निजी बस ऑपरेटर मनमानी कर रहे हैं। परिवहन विभाग की लापरवाही के बीच अब बसें यात्री वाहन कम, मालवाहक वाहन ज्यादा नजर आने लगी हैं।

हालत यह है कि सीटों पर यात्रियों के बजाय भारी बोरियां, पार्सल और डिब्बे रखे जा रहे हैं। बसों की छत और नीचे बने बॉक्स में भी भारी मात्रा में माल ठूंसा जा रहा है। यह खेल सवारियों की आड़ में खुलेआम चल रहा है, लेकिन विभाग ने आंखें मूंद रखी हैं। परिवहन नियमों के अनुसार किसी भी यात्री बस में आग बुझाने के यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट और प्रशिक्षित चालक-परिचालक होना अनिवार्य है, परंतु ज्यादातर बसों में ये बुनियादी सुरक्षा मानक नहीं मिलते। जिले में चलने वाली निजी बसों की आरटीओ अमला जांच करने की बजाय केवल कागजी खानापूर्ति में जुटा रहता है। आरटीओ द्वारा न तो अचानक निरीक्षण होता है और न ही माल ढुलाई करने वाली बसों पर कोई ठोस कार्रवाई। ऐसे में कंडम बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे यात्रियों की जान खतरे में रहती है। निजी बस चलाने वाले कई ड्राइवरों के पास उचित प्रशिक्षण तक नहीं हैं, फिर भी वे रोजाना सैकड़ों यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसें चला रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जब बस में जगह नहीं रहती, तब भी चालक और स्टाफ माल उठाने से नहीं चूकते। कई बार बसों में भरे वजन के कारण इंजन ओवरहीट हो जाते हैं और सड़क पर खराब हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

बसों में नियम और आवश्यकताएं

0 सभी यात्री वाहनों में अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य है।

0 स्लीपर या एसी बसों में एक से अधिक अग्निशामक यंत्र जरूरी हैं।

0 आपातकालीन दरवाजा और निकासी खिड़कियों को तोड़ने के लिए हथौड़े जैसा औजार (हैमर) आवश्यक है।

0 यात्रियों को चोट लगने पर राहत देने के लिए बसों में फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है।

0 चालक और परिचालकों को अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

0 सभी तरह की यात्री बसों में मौजूद सुरक्षा उपकरणों की समय-समय पर जांच होनी चाहिए।

राशिफल

मेष राशि: आज किसी भी काम को पूरा करने में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो उस काम में कुछ कमियां रह जायेंगी। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में कम और मोबाईल पर ज्यादा रहेगा। आज आप अपने फिजूल खर्चों पर काबू बनाये रखें। आज कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपके मन में कुछ नए आइडिया आयेंगे।

वृष राशि: आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। पहले से ही किये हुए निवेश का आज आपको फायदा मिलेगा। आज आप किसी खास मित्र की मदद करेंगे। आज आपके कारोबार में बड़ा बदलाव आयेगा। लम्बे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित समस्या से छुटकारा मिलेगा। आज आप अपने मेहनत से कठिन से कठिन कार्य को पूरा करने में सफल होंगे।

मिथुन राशि: आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आप आपने भविष्य को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर ध्यान देंगे। आज के दिन कोई करीबी रिश्तेदार आपकी खुशियों को दोगना कर देगा। आज घर के बड़ों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के नए अवसर प्राप्त होंगे।

कर्क राशि: आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको अपनी बचत में से कुछ पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है। आज आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, जो उनके भविष्य में उन्हे काम आयेगा। आज जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है।

सिंह राशि: आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आज आप जिस काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो आसानी से पूरा हो जायेगा। किसी दोस्त से मुलाकात आपको फायदा दिला सकती है। आज परिवार के लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। आज आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करेंगे, इसमें पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा।

कन्या राशि: आज कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। दूसरों की सलाह पर ध्यान देंगे, तो वह आपके लिये फायदेमंद साबित होगा। छात्रों को आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज आपको ऑफिस के किसी काम से यात्रा करना पड़ेगा। कारोबारियों को आज उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। नवविवाहित दंपत्ति आज परिवार वालों को खुशी की वजह देंगे।

तुला राशि: आज आपके जीवन में कई नए बदलाव आयेंगे, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे। सोशल मीडिया पर नए लोगों से आपकी दोस्ती होगी। आज समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी, तरक्की के नए अवसर आपके सामने आयेंगे। दोस्तों के साथ मिलकर नया व्यापार शुरू करने की सोचेंगे। जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आज उन्हें अच्छा क्लाइंट मिलेगा।

वृश्चिक राशि: आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। छात्रों को आज कहीं से करियर संबंधी शुभ सूचना मिलेगी, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बनेगा। जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनायेंगे जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आयेगी। बच्चे माताङ्पिता के साथ पार्क में जाने की जिद्द करेंगे।

धनु राशि:आज आपका दिन अच्छा रहेगा। घर के रूके हुए सभी काम आज आसानी से पूरे होंगे। किसी बात को लेकर आपके मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगो को किसी अच्छी कपंनी से जॉब का ऑफर आयेगा।

मकर राशि: आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज कार्यों को पूरा होने में कुछ अधिक समय लगेगा। इस राशि के जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते है आज उन्हें बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज कार्यों को पूरा करने में परिवार वालो का सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी पर भरोसा बनाये रखेने से, रिश्तों में मजबूती आयेगी।

कुंभ राशि: आज आपका दिन ठीक-ठाक रहेगा। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरुरत है। आज कुछ पुराने दोस्तों से फ़ोन पर लम्बी बात होगी, जिनके के साथ आप अपनी पुरानी यादें भी ताजा करेंगे। आज आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करेंगे।

मीन राशि: आज आपका दिन शानदार रहेगा। छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें गुरुओं का सहयोग प्राप्त होगा। आज घर पर थोड़े व्यावहारिक रहने की कोशिश करेंगे, जिससे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि के जो लोग वकील हैं, उनको कोई नया केस मिलेगा।

कलेक्टर ने विद्युत गृह विद्यालय में बीएलओ को दिए जा रहे एसआईआर प्रशिक्षण का किया निरीक्षण

बीएलओ को प्रशिक्षण में विशेष ध्यान देने व बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त करने के दिए निर्देश

कोरबा (छ.ग.गौरव) । भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के लिए मतदाता सूची के वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ घोषित की गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में विभिन्न प्रपत्रो की प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य 03 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। ततपश्चात 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा डोर टू डोर विजिट कर सर्वेक्षण एवं सूचीकरण कार्य संचालित किया जाएगा। इस हेतु जिले के सभी विधानसभाओं में बीएलओ को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा कोरबा नगरीय क्षेत्र के विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21, कोरबा अंतर्गत नियुक्त बीएलओ के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। उन्होंने प्रशिक्षण में उपस्थित सभी बीएलओ को इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना छूटे ,तथा कोई भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में ना रहे। सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एसआईआर कार्यक्रम में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु आप सभी प्रशिक्षण में विशेष ध्यान दें, सभी बारीकियों का गहनता से जानकारी प्राप्त कर अपनी शंकाओ एवं सर्वे के दौरान जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का भी निराकरण प्राप्त कर लें। इस दौरान एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलांगे, मास्टर ट्रेनर श्री गौरव शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर को विभिन्न प्रपत्रों , डोर टू डोर सर्वे कार्य, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, स्थानांतरित करने, काटने हेतु उपयोगी प्रपत्रों के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण में बीएलओ को जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त सर्वे अवधि में बीएलओ प्रत्येक घर के मतदाताओं को गणना पत्रक की दो प्रति बाटेंगे तथा उसको भरने में मतदाताओं को सहयोग भी करेंगे। यदि मतदाता अनुपस्थित हो तो गणना पत्र को घर पर छोड़कर एक सूचना घर के दरवाजे पर चिपकाएंगे जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि बूथ लेवल ऑफिसर तीन अलग-अलग तिथियां में गणना पत्रक लेने के लिए पुन: आएंगे। गणना पत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे एवम दूसरी प्रति में मतदाताओं को पावती देंगे। गणना पत्रक पूर्व मुद्रित होगा जिसमें मतदाता की जानकारी मुदित होगी। मतदाताओं का वर्गीकरण अलग-अलग श्रेणी में करते हुए जिसमें सामान्य मतदाता ऐसे मतदाता होंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में भी हो एवं 2003 के गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची में भी हो । इसी प्रकार कुछ मतदाता जिनका नाम 2025 की सूची में तो है, परंतु उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, परंतु उनके रिश्तेदार जैसे माता या पिता का नाम उस सूची में हो उनका चिन्हांकन करते हुए पत्रक भरा जाएगा । ऐसे दोनों प्रकार के मतदाताओं को कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2003 के मतदाता सूची की स्क्रीनशॉट देनी होगी। जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ होगा एवं उनका नाम 2003 की सूची में नहीं है उन्हें 12 विहित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के मध्य हुआ हो उन्हें स्वयं के पहचान के लिए 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक के दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी । इसी प्रकार 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिए समस्त मतदाताओं को अपने स्वयं की पहचान के लिए कोई एक दस्तावेज के साथ-साथ माता एवं पिता दोनों के पहचान के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

पेंशन योजनाओं के शेष बचे हितग्राहियों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं

कोरबा (छ.ग.गौरव) । आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर अपर आयुक्त विनय मिश्रा ने निगम के समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने जोन के अंतर्गत ऐसे शेष बचे सभी पेंशन हितग्राहियों, जिनका सत्यापन अभी तक नहीं किया जा सका है, का वार्षिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराएं ताकि पेंशन हितग्राहियों को नियमित पेंशन की प्राप्ति में किसी प्रकार का अवरोध उपस्थित न होने पाएं।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित केन्द्रीय पेंशन योजनाओं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के पेंशन हितग्राहियों का वार्षिक सत्यापन मोबाईल एप के माध्यम से किए जाने हेतु पूर्व में दिए गए निर्देशों के तहत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य निगम के सभी जोन में आयोजित शिविरों के माध्यम से कराया गया था किन्तु कुछ हितग्राहियों का सत्यापन कार्य किया जाना अभी भी शेष है। शतप्रतिशत हितग्राहियों का सत्यापन कार्य सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर अपर आयुक्त श्री विनय मिश्रा ने समस्त जोन उप प्रभारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने क्षेत्रांतर्गत इस हेतु पुन: मुनादी कराएं तथा हितग्राहियों को उनके आधार कार्ड व मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए सत्यापन का कार्य पूरा कराएं ताकि हितग्राहियों को नियमित पेंशन प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या पैदा न हों तथा उन्हें नियमित रूप से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित हो सके। वहीं हितग्राहियों से भी अपील की गई है कि वे वार्षिक सत्यापन कार्य में सहयोग करें तथा अनिवार्य रूप से अपना सतयापन करा लें ताकि उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त होने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

छत्तीसगढ़ की नई पहचान

नवीन विधानसभा भवन का

लोकार्पण

यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय

श्री नरेन्द्र मोदी जी

के कर कमलों से

होने पर समस्त छत्तीसगढ़वासियों को

हार्दिक शुभकामनाएं

शनिवार, 01 नवंबर 2025

नवीन विधानसभा परिसर, नया रायपुर

विनीत : छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

संवाद-45736/106

सम्पादकीय...

जहरीली हवा में घुटती सांसें

दशकों से मीडिया व पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोग तथा संगठन, जिस प्रदूषण संकट के प्रति चेताते रहे हैं, उसके घातक परिणाम अब साफ सामने नजर आने लगे हैं। विडंबना यह है कि देश की राजधानी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही नहीं, अब देश के तमाम बड़े-छोटे शहरों से भी जानलेवा प्रदूषण की खबरें आ रही हैं। इस घातक व मारक संकट की पुष्टि बहुचर्चित मेडिकल जर्नल लैंसेट की हालिया रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट दावा करती है कि देश की हवा में 2010 की तुलना में साल 2022 तक प्रदूषणवाहक पीएम 2.5 कणों की मात्रा में 38 फीसदी तक का बढ़ावा हुआ है। जिसका घातक प्रभाव यह है कि करीब सत्रह लाख लोग असमय काल-कवलित हो चले हैं। इससे होने वाला आर्थिक नुकसान अलग है। यह कहना कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। बहुत संभव है कि सरकारें इन आंकड़ों पर सहमति न जताएं, लेकिन दीपावली के बाद दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के विभिन्न शहरों में प्रदूषण जिस घातक स्तर तक पहुंचा है, वह हालात के गंभीर होने की ओर इशारा तो करता ही है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दिल्ली को दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का खिताब भी दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अस्पतालों में प्रदूषणजनित रोगों का उपचार कराने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। जीवन के संघर्ष में रोजी-रोटी की कवायद में जुटे लोगों को यह अहसास भी नहीं होता है कि वे दिन में कितनी जहरीली हवा निगल रहे हैं। हमारे शहर केंद्रित विकास की विसंगितयां भी शहरों में प्रदूषण का दायरा बढ़ा रही हैं। शहरों में उगते कंक्रीट के जंगल न केवल हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं बल्कि वाहनों के सैलाब को भी बढ़ावा दे रहे हैं। विडंबना यह है कि इसके बावजूद राजनीतिक दलों व सरकारों में वह इच्छाशक्ति नजर नहीं आती, जो इस संकट के कारगर समाधान की राह दिखाती हो। निश्चित तौर पर प्रदूषण संकट की यह जानलेवा स्थिति हमें शर्मसार करने वाली है। यह हमारी सामूहिक विफलता की तसवीर भी उकेरती है। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली व निकटवर्ती शहरों में जो प्रदूषण का बड़ा संकट दिखायी देता है, आखिर उसे साल भर सतर्कता के साथ क्यों नहीं देखा जाता। देश में आर्थिक असमानता व गरीबी के चलते लाखों लोग व बच्चे उन अस्वस्थकारी परिस्थितियों में काम करने को बाध्य हैं, जो कालांतर जानलेवा रोगों का सबब बनती हैं। देश में करोड़ों बाल श्रमिक पटाखा, कालीन और अन्य सांस के रोगों का संकट बढ़ाने वाले उद्योगों में काम कर रहे हैं। व्यवस्था का भ्रष्टाचार नियामक एजेंसियों को हिलने तक नहीं देता। दरअसल, यह प्रदूषण मौसमी बदलाव, पटाखों या पराली जलाने से ही नहीं पैदा होता। दरअसल, इसके मूल में शासन-प्रशासन की वह विफलता भी शामिल है, जो वातावरण को जहरीला बनाने वाले उद्योगों तथा निर्माण में उड़ने वाली धूल की सतर्क निगरानी नहीं करती। दरअसल, हमारे जीवन की कृत्रिमता व सुविधाभोगी जीवनशैली ने उन घातक गैसों को बढ़ावा दिया जो ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण की कारक बनती हैं। इस समस्या का एक पहलू यह भी है कि देश की जनता इस आसन्न संकट के प्रति लगातार उदासीन बनी रहती है। वह चुनावों के दौरान न तो राजनेताओं पर इस संकट के समाधान के लिये दबाव बनाती है और न ही निजी जीवन में ऐसी कोई पहल करती है। इस तरह कहीं न कहीं इस प्रदूषण वृद्धि में हमारी भागीदारी बनी हुई है। अब भले ही कार्बन उत्सर्जित करने वाले ईंधन के उपयोग में कमी आई है, लेकिन अभी भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। हम निजी जीवन में जितनी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, उतना ही प्रदूषण धीरे-धीरे कम होता जाएगा। जनता को शासन-प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि वह समय रहते प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रयास करे। व्यक्ति के तौर पर हमें पटाखे व पराली जलाने वालों की निगरानी करनी होगी, ताकि प्रदूषण का स्तर कम करने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

जागरुकता और कानून सख्ती से ही रुकेंगी ऑनर किलिंग

योगेंद्र योगी

ऑनर किलिंग या लिंग आधारित हिंसा देश के राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि नेता वोट बैंक की राजनीति के कारण आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए राजनीति, शैक्षिक और कानून के जरिए जागरुकता लाने की जरुरत है।

गुरुग्राम में पिता दीपक यादव ने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मार कर हत्या की थी। पिता और बेटी के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद चल रहा था। चार्जशीट में आरोपी पिता दीपक ने बताया कि उसके गांव के लोग उसे टोकते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। बेटी के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। इससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इसलिए बेटी की हत्या कर दी। अभी तक यही माना जाता रहा है कि ऑनर किलिंग के ज्यादातर मामले गरीब और पिछड़ेपन के कारण ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं, किन्तु गुरुग्राम में हुई इस घटना ने साबित कर दिया कि कुछ हद तक यह मानसिकता शिक्षित लोगों के बीच शहरों में भी व्याप्त है। देश एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था सहित दूसरे क्षेत्रों में छलांग लगा रहा है, वहीं आदिमयुगीन इस तरह की वारदात से भारत की छवि कलंकित हो रही है।

दिल्ली की पत्रकार निरुपमा पाठक की मौत के साथ ऑनर किलिंग का मुद्दा सुर्खियों में आया था। आरोप था कि परिवार ने उसे इसलिए मार डाला क्योंकि वह गर्भवती थीं और अपनी जाति के बाहर के व्यक्ति से शादी करने की योजना बना रही थीं। इसके बाद राजधानी में संदिग्ध ऑनर किलिंग के दो और मामले सामने आए। हालांकि राजधानी में ऑनर किलिंग की घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन भारत के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आम हैं। ऑनर किलिंग के पीछे मूल कारण यह विचार है कि परिवार का सम्मान महिला की पवित्रता से जुड़ा होता है। ऑनर किलिंग के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वैवाहिक बेवफाई, विवाह से पहले यौन संबंध, अनुचित संबंध, तय शादी से इनकार करना या यहां तक कि बलात्कार भी। भारत में ऑनर किलिंग तब होती है जब कोई जोड़ा अपनी जाति या धर्म के बाहर शादी करता है ।

करनाल की एक सत्र अदालत ने एक खाप पंचायत के आदेश के विरुद्ध विवाह करने वाले एक युवा जोड़े की हत्या के लिए पाँच लोगों को पहली बार मृत्युदंड सुनाया। अदालत ने खाप पंचायत के उस सदस्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसने विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था और जो हत्या के समय मौजूद था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और आठ राज्यों को नोटिस जारी कर ऑनर किलिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की व्याख्या करने को कहा था। सरकार ने सतर्क रुख अपनाते हुए तत्कालीन कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली के भारतीय दंड संहिता में संशोधन और खाप पंचायतों (जाति-आधारित संविधानेतर संस्थाएँ) पर लगाम लगाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्यों से परामर्श करने और ऑनर किलिंग को एक सामाजिक बुराई मानने वाले एक विशेष कानून को लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय लिया था।

तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में, जहाँ दलित समुदायों का अपेक्षाकृत अधिक सशक्तिकरण हुआ है, अंतर्जातीय विवाहों की दर भी अधिक दर्ज की गई है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण द्वितीय के अनुसार, अंतर्जातीय विवाहों की राष्ट्रीय दर लगभग 5% है, लेकिन सशक्त दलित आबादी वाले राज्यों में यह दर अधिक है। विडंबना यह है कि इन्हीं राज्यों में ऑनर किलिंग की घटनाएँ भी बढ़ी हैं। यह विरोधाभास एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। ऑनर किलिंग वहाँ नहीं होती जहाँ जातिवाद सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, बल्कि वहाँ होती है जहाँ यह सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। जिन राज्यों में उत्पीड़ित लोग अभी भी अपनी 'यथास्थिति' बनाए हुए हैं, वहाँ हिंसा कम होती है, इसलिए नहीं कि जातिवाद मौजूद नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसे चुनौती नहीं दी जाती। संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न रिपोर्टों में ऑनर किलिंग को विश्व में एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया गया है, जो कि लैंगिक असमानता और पुरुष प्रधान समाजों में गहराई से निहित है। रिपोर्टों के अनुमान के अनुसार, हर साल दुनिया भर में लगभग 5,000 ऑनर किलिंग होती हैं, जिनमें 20% मामले भारत में होते हैं, हालाँकि सटीक आंकड़े अज्ञात हैं क्योंकि सभी देश आधिकारिक डेटा नहीं रखते हैं। ये रिपोर्टें बताती हैं कि यह सिर्फ़ भारत की ही नहीं, बल्कि मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और यूरोप के देशों सहित अन्य क्षेत्रों की भी एक वैश्विक समस्या है। यह समस्या मुख्य रूप से मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में व्यापक है, लेकिन बांग्लादेश, ब्राजील, कनाडा, इक्वाडोर, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, इटली, मोरक्को, पाकिस्तान, स्वीडन, सीरिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विभिन्न देशों में भी होती है।

कई देशों में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अक्सर इन कानूनों का पालन नहीं किया जाता है या ये अपर्याप्त हैं। महिलाओं और लड़कियों के अलावा, एलजीबीटी समुदाय के लोग भी ऑनर किलिंग का शिकार हो रहे हैं। रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह समस्या मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और विशेष रूप से भारत में संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है। ऑनर किलिंग अन्य प्रकार की लैंगिक-आधारित हिंसा का ही एक रूप है, जैसे कि एसिड अटैक, यातना और अपहरण। भारत में जाति एक दोराहे पर खड़ी है। एक ओर, हम हिंसक प्रतिक्रियाएँ और ऑनलाइन महिमामंडन देख रहे हैं। दूसरी ओर, हम ऑनर किलिंग के खिलाफ मज़बूत लोकतांत्रिक आवाज़ें और सामाजिक मूल्यों से धीरे-धीरे दूर होती एक नई पीढ़ी देख रहे हैं। भारत में जाति और लिंगभेद आधारित समस्या नहीं गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक परिघटना है। जाति केवल इसलिए नहीं टिकती और फलती-फूलती है क्योंकि व्यक्ति उस पर ज़ोर देते हैं, बल्कि इसलिए भी कि परिवार, समुदाय और समूची सामाजिक संरचनाएँ, जानबूझकर या अनजाने में, उसे लागू और वैध बनाती रहती हैं। जातिगत सीमाओं को पार करने वाले प्रेम संबंध, खासकर वे जो दलित पुरुषों और प्रभुत्वशाली जाति की महिलाओं के बीच होते हैं। ये संबंध केवल प्रेम या विद्रोह का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि सदियों पुरानी जातिगत पदानुक्रमों को सीधी चुनौती देते हैं। ऑनर किलिंग या लिंग आधारित हिंसा देश के राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि नेता वोट बैंक की राजनीति के कारण आग में घी डालने का काम करते हैं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं को रोकने के लिए राजनीति, शैक्षिक और कानून के जरिए जागरुकता लाने की जरुरत है।

(यह लेखक के अपने विचार है)

एसआईआर शुरू करने में राजनीतिक बाधा

अजीत द्विवेदी

चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर चुका है। अगले साल चुनाव वाले चार राज्यों के साथ साथ 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चलेगी। इन 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है और चार नवंबर से पहले चरण यानी मतगणना प्रपत्र भरे जाने की शुरुआत होगी। नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और एक महीने तक आपत्ति, दावे लिए जाएंगे। सात जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन 12 राज्यों से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का बिहार में परीक्षण किया था, जो सफल रहा है।

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस कामयाबी का जिक्र भी किया। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया कि बिहार में उसके काम में कितनी बाधाएं आईं और राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को कैसी लड़ाई लड़नी पड़ी। बिहार में एसआईआर को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा उसकी सुनवाई अभी चल ही रही है। इसी आधार पर कई पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारधीन है और अंतिम फैसला नहीं आया है तो चुनाव आयोग को दूसरे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया नहीं शुरू करनी चाहिए थी। हालांकि उसमें आयोग यह तर्क दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में भी एसआईआर पर रोक नहीं लगाई थी इसलिए दूसरे राज्य में इसे शुरू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

ठीक बात है कि दूसरे राज्य में इसे शुरू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है लेकिन राजनीतिक बाधा है और कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। जैसे बिहार में 10 हजार ऐसे लोगों के नाम कटे हैं, जिनको नाम काटने वाली किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसी तरह स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाने की जो श्रेणी है उसे लेकर भी आपत्ति है क्योंकि स्थायी रूप से बहुत कम लोग शिफ्ट होते हैं। ज्यादातर लोग अंततः वापस लौटते हैं और अपने स्थायी पते के ही वासी होते हैं। कोरोना के समय या दूसरे आर्थिक संकट के समय यह देखने को मिला है कि लोग अपने घरों को लौटे हैं।

स्थायी रूप से शिफ्ट हो जाने वाली श्रेणी में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। तभी चुनाव आयोग को बहुत सावधानी बरतने की जरुरत होगी ताकि ऐसे लोगों के नाम नहीं कटें, जो अपने स्थायी पते पर नहीं रहते हैं लेकिन दूसरी जगह के मतदाता नहीं हैं और स्थायी पते पर ही मतदाता बने रहना चाहते हैं। ऐसे प्रवासियों के लिए बूथ लेवल अधिकारी के तीन बार उसके पते पर जाने का नियम पर्याप्त नहीं है। बिहार में ऐसा देखने को मिला कि बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ तीन बार तो छोड़िए एक बार भी लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा। कई जगह सफाईकर्मी या दूसरे कर्मचारियों के हाथों मतगणना प्रपत्र भेजे गए। खाली घरों के आसपास ज्यादा से ज्यादा एक बार पूछताछ हुई और नाम काट दिया गया। अस्थायी रूप से कहीं गए लोगों के भी नाम कटे।

चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया उसने मतदाता सूची की सफाई के लिए चलाई है, लोगों के मताधिकार छीनने के लिए नहीं। उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि मृत मतदाताओं या एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज नाम वाले मतदाताओं के नाम काटे लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वास्तविक मतदाता का नाम नहीं कटना चाहिए। बिहार के अनुभव के आधार पर उसे इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए सहज और सरल बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जिस तरह की खबरें और तस्वीरें बिहार से एसआईआर की आईं वैसी दूसरे राज्यों से नहीं आनी चाहिए। आयोग को भी पता है कि कैसे बूथ लेवल अधिकारियों ने अपने घरों में बैठ कर मतगणना प्रपत्र भरे और उन्हें जमा कर दिया। कैसे पहले से भरे हुए दो मतगणना प्रपत्र की जगह मतदाताओं को एक प्रपत्र दिया गया। मतदाताओं पर छोड़ दिया गया कि वे इसकी फोटोकॉपी कराएं। मतदाताओं की तस्वीरों के मामले में भी कई तरह की गड़बड़ियां हुईं। नाम, पता, लिंग आदि की विसंगतियां तो अब भी बड़ी संख्या में मतदाता सूची में हैं। इनका भी ध्यान रखने की जरुरत है।

आधार के मामले में अब भी स्पष्टता नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने का निर्देश दिया है। लेकिन पहले से ही यह स्थिति स्पष्ट है कि आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज है और यह नागरिकता प्रमाणित करने का दस्तावेज नहीं हो सकता है।

वोट चोरी की सच्चाई सामने आनी चाहिए

कलबुर्गी स्थित जिस कॉल सेंटर की सेवा इसके लिए ली गई, उसे मतदाता के नाम को काटने की हर अर्जी के लिए 80 रुपए दिए गए। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच ऐसी कुल 6,018 अर्जियां दी गईं।

कर्नाटक पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) इस नतीजे पर पहुंचा है कि राज्य के अलांद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले नियोजित ढंग से मतदाताओं के नाम मतदाता कटवाए गए। ऐसा ऑनलाइन माध्यम से हुआ। एसआईटी इस निष्कर्ष पर है कि कलबुर्गी स्थित जिस कॉल सेंटर की सेवा इसके लिए ली गई, उसे मतदाता के नाम को काटने की हर अर्जी के लिए 80 रुपए दिए गए। दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच ऐसी कुल 6,018 अर्जियां दी गईं। इस तरह कुल लगभग 4.80 लाख रुपये का भुगतान किया गया। संदेह है कि यह रकम 2023 में अलांद सीट पर पराजित हुए भाजपा उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार की तरफ से दी गई। कर्नाटक पुलिस ने पिछले हफ्ते गुट्टेदार के घर पर छापा मारा था।

बहरहाल, सिर्फ 24 ऐसे वास्तविक मतदाताओं की पुष्टि हुई है, जिनके नाम इस प्रयास के कारण मतदाता सूची से हटे। बाकी मतदाता पहले ही उस क्षेत्र से जा चुके थे- यानी उनका नाम कटना जायज ही था। मगर 24 मतदाताओं के नाम कटना भी बड़ा मुद्दा है। इससे पुष्टि होती है कि इस तरह के सुनियोजित प्रयास हुए और ऐसा ऑनलाइन माध्यम से तीसरे पक्ष की तरफ से किया गया। यही इल्जाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगाया था। उनके आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी मतदाता का नाम काटने की अर्जी सिर्फ आधार से जुड़े मोबाइल फोन नंबर से ही दी जा सकेगी।

इस तरह उम्मीद जगी है कि भविष्य में इस तरह की वोट चोरी को रोका जा सकेगा। परंतु, जैसाकि बाद में राहुल गांधी ने कहा था, पहले हुई वोट चोरी की सच्चाई सामने आनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखाई है। उससे अपेक्षित है कि कर्नाटक एसआईटी जांच में पूरा सहयोग करे और इस प्रकरण को इसके अंजाम तक पहुंचाए। भारत की चुनाव प्रक्रिया पर पहले से कई सवाल हैं।

विद्युत ऊर्जा : रजत वर्ष में स्वर्ण काल की तैयारी

विकास शर्मा
प्रबंधक
जनसंपर्क एवं
औद्योगिक संबंध
सीडीपीडीसीएल

राज्य स्थापना की रजत जयंती के उत्साह के बीच प्रदेश के विकास को विभिन्न पैमानों पर मापा जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है कि वर्तमान की जेन - जी और जेन - अल्फा को पता होना चाहिए कि उल्लास के पीछे का यथार्थ क्या है ? छत्तीसगढ़ ने बीते ढ़ाई दशकों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आधारभूत क्षेत्रों में देश के कई प्रदेशों से हम बहुत बेहतर कर पा रहे हैं यह अहसास उत्साहजनक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार जैसे प्रमुख पैमानों में राज्य की उपलब्धियों को मजबूत आधार देती है विद्युत ऊर्जा। प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का विकास सभी को चमत्कृत और उज्ज्वल भविष्य का विश्वास दिलाता है।

सफर में कई मील के पत्थर

राज्य गठन उपरांत ढाई दशक में ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति की यात्रा में कई मील के पत्थर स्थापित हुए हैं। इस दौरान राज्य में 300 प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता तो बढ़े ही पर बढ़ती संख्या के साथ गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करना विशेष उपलब्धि से कम नहीं। महज 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 5 गुना वृद्धि के साथ आज 30,000 मेगावॉट की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ली गई है। विद्युत की अधिकतम मांग 500 प्रतिशत बढ़कर 7000 मेगावॉट के आँकड़े को पार कर आगे निकल चुकी है। 800 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 6 लाख स्थाई कृषि पम्प हों या औद्योगिक उपभोक्ताओं में ढाई गुना बढ़ोतरी के साथ 41 हजार औद्योगिक इकाइयाँ, सभी राज्य के विकास को आधार प्रदान कर रहे हैं। 2211 यूनिट खपत के साथ प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में पूरे देश के पाँच प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल है जो गौरव की बात है और साथ ही ये आँकड़े भविष्य की प्रगति और समृद्धि के लिए हमें आश्वस्त भी करते हैं।

विकसित भारत के लक्ष्य के साथ कदमताल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना में ऊर्जा क्षेत्र की सबसे अहम भूमिका है और ऐसे में अगले तीन दशक की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करना व्यापक कार्ययोजना से ही संभव है। सच तो यह है कि स्थापना के 25 वें वर्ष में जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे वो हमारी स्थापना के 50 वें वर्ष को अधिक सुखमय और समृद्ध बनाने का काम करेगा। देश में विद्युत की खपत अगले दस वर्षों तक लगभग 8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और वर्ष 2047 में देश में अधिकतम मांग 750 गीगावॉट तक जा पहुंचेगी। ऐसे में मिशन मोड पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में 270 गीगावॉट है।

ताप विद्युत उत्पादन की सीमाओं को समझते हुए तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए वर्ष 2070 के लक्ष्य के बीच नवीकरणीय ऊर्जा समेत अन्य विकल्पों पर देशभर में तेजी से काम किया जा रहा है। ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं के बीच देश की निगाह छत्तीसगढ़ की ओर टिकी हुई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता 30 हजार मेगावॉट है। ऊर्जा उत्पादन की नई पारी में ताप के साथ हरित ऊर्जा को महत्व दिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ ने विद्युत विकास की ऐसी रूपरेखा तैयार की है जिससे ऊर्जा की निरंतरता बनी रहे। राज्य बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ ऊर्जा समृद्धि प्राप्त करने की इस दिशा में बढ़ चुका है। इसके तहत इसी वर्ष तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करने में पहली सफलता अर्जित की गई । आने वाले एक दशक में प्रदेश में 31 हजार मेगावॉट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

ऊर्जा के साथ रोजगार भी

राज्य की स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी (सीएसपीजीसीएल) , सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादक नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) , टिहरी हाइडल पॉवर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन(टीएचडीसी), सतलज जल विद्युत निगम लि.(एसजेवीएन) सहित निजी क्षेत्र की अडानी पॉवर लिमिटेड एवं अन्य बड़े निवेशकों ने ताप समेत पन बिजली के क्षेत्र में 17 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिए समझौता किया है। इस निवेश से प्रदेश के समग्र विकास को आधार मिलेगा। ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के आने से औद्योगीकरण की संभावनाएं बढ़ती हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं।

परमाणु ,पन और सौर ऊर्जा में बढ़ी संभावना

गैर- जीवाश्म ईंधन के तौर पर सौर ऊर्जा,पन बिजली, पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया जा रहा है। इन ऊर्जा स्रोतों में नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं जो अंततः विद्युत मांग की पूर्ति पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना कर सके। प्रदेश में सरायपाली के पास यूरेनियम भंडार मिलने के बाद यहाँ परमाणु ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं पर विचार शुरू हुआ । अब एनटीपीसी के सहयोग से 4200 मेगावॉट विद्युत उत्पादन करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह प्रदेश में पहली परमाणु विद्युत उत्पादन इकाई होगी। इसके अलावा पन विद्युत परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पम्प स्टोरेज तकनीक की मदद से 7500 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है।

सौर ऊर्जा सबसे सुलभ विदयुत विकल्प है। ऐसे में इसे बड़े उत्पादन संयंत्रों तक सीमित न रखकर आम उपभोक्ता को विदयुत उत्पादक बनाने की योजना केन्द्र सरकार ने चलाई है। महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को और अधिक आकर्षक बनाते हुए केन्द्र के साथ राज्य सरकार भी अब वित्तीय मदद पहुँचाकर विद्युत उत्पादन में आम लोगों की भूमिका बढ़ाना चाह रही है।

मजबूत ऊर्जा अधोसंरचना पर बल

आज की बिजली की आवश्यकताओं को समझते हुए उत्पादित बिजली का समुचित पारेषण और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पारेषण और वितरण क्षेत्र में भी राज्य बड़ा निवेश कर रही है। असल में पारेषण प्रणाली की मजबूती के बगैर विद्युत मांग की आपूर्ति का दबाव नहीं थामा जा सकता है। प्रदेश में आज 14 हजार 249 सर्किट किलोमीटर की अतिऊच्चदाब लाईने हैं जिसकी क्षमता 25 हजार 617 एमव्हीए है। अगले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में 1700 मेगावॉट अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क का विकास किया जाना है। इससे हमारे ताप विद्युत की निकासी को सुगम बनाया जा सकेगा।

गौरव का एहसास, दशकों का इतिहास

छत्तीसगढ़ में विद्युत ऊर्जा का इतिहास तो एक शताब्दी से कुछ ऊपर का है पर ऊर्जा की सार्वजनिक उपयोगिता, सुलभता और आमजन के जीवन को रोशन करने का इतिहास लगभग सात दशक में फैला है। एक प्रदेश के लिए 25 वर्षों की विकास यात्रा बहुत लंबी नहीं लेकिन उसकी दिशा तय करने में यह शुरूआती कालखण्ड सबसे महत्वपूर्ण है। विद्युत क्षेत्र में 25 वर्षों के इस कालखण्ड में जो विकास हुआ है उसे हम अपने स्वर्ण काल की तैयारी के रूप में दर्ज कर सकते हैं।

दैनिक
छत्तीसगढ़ गौरव

इंदौर स्वीट्स
नमकीन और मिठाईयों की लंबी श्रृंखला के बाद
अब केशर कुल्फी और दही कचौड़ी
हमारा विश्वास हैं
एक बार खायेंगें, बार-बार आयेंगें...
पावर हाऊस रोड, कोरबा
फोन-222833,222733

कोरबा, शनिवार 01 नवंबर 2025 website:- chhattisgarhgaurav.in

'त्रिशूल' की ताकत देख कांपा पाकिस्तान, पाक मीडिया चैनलों ने किया दावा- भारत ने 300 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात कीं

नई दिल्ली,01 नवंबर (एजेंसी)। भारत की पश्चिमी सीमाओं पर 'त्रिशूल' नामक सैन्य अभ्यास ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर संवेदनशील सर क्रीक क्षेत्र तक भारतीय सेनाओं की यह विशालकाय तैयारी न केवल रणनीतिक रूप से सशक्त संदेश देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नया भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करता, बल्कि आक्रामक तत्परता की स्थिति में है।

हम आपको बता दें कि 30 अक्तूबर 2025 से शुरू हुआ यह 12 दिवसीय त्रि-सेवा अभ्यास सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन है। लगभग 20,000 सैनिक, टी-90 टैंक, राफेल और सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान, आकाश व ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियाँ, नौसैनिक युद्धपोत और विशेष बल कमांडो इस अभ्यास का हिस्सा हैं। 'त्रिशूल' का उद्देश्य स्पष्ट है— संयुक्त युद्ध क्षमता, तीव्र आक्रामक प्रतिक्रिया और किसी भी संभावित युद्ध परिदृश्य में समन्वित जवाबी हमला करने की योग्यता को परखना। मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' से सीखे गए सबक अब इस अभ्यास में परिष्कृत रूप में दिख रहे हैं।

दूसरी ओर, 'त्रिशूल' शुरू होते ही पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक टीवी स्टूडियो में 'घबराहट' और 'आपात तैयारी' की खबरें छा गईं। पाकिस्तान की वायुसेना ने अपने एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया, ह्लह्ल्रू्ल्ह्य (एयरस्पेस प्रतिबंध) जारी किए और सीमा के पास लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। पाकिस्तानी विश्लेषकों का यह स्वीकार करना कि 'भारतीय अभ्यास की स्केल ने सुरक्षा प्रतिष्ठान में घबराहट फैला दी है'— दरअसल भारत के रणनीतिक वर्चस्व की अनकही स्वीकारोक्ति है। जिस देश के लिए कुछ साल पहले 'सर्जिकल स्ट्राइक' और 'बालाकोट एयर स्ट्राइक' केवल चेतावनी थीं, आज वह भारत के सैन्य अभ्यास भर से मनोवैज्ञानिक दबाव में है।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों ने दावा किया कि भारत '300 ब्रह्मोस मिसाइलें' तैनात कर रहा है। देखा जाये तो यह भ्रामक प्रचार है। वास्तविकता यह है कि भारत के पास कुल मिलाकर 1,500 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों का भंडार है, परंतु किसी एक क्षेत्र में इतनी संख्या में तैनाती का प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल, भारतीय नौसेना का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपने पूरे बेड़े में 300 ब्रह्मोस मिसाइलों के एक साथ प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना है। यह एक दीर्घकालिक आधुनिकीकरण योजना है, न कि 'त्रिशूल' अभ्यास की वास्तविक तैनाती। पाकिस्तान का '300 ब्रह्मोस' वाला दावा उसी मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का हिस्सा है, जो उसके पूरे सैन्य तंत्र को जकड़ चुकी है। जब किसी देश का डर उसके तथ्यों पर भारी पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि शक्ति संतुलन किस दिशा में झुक चुका है। देखा जाये तो 'त्रिशूल' से पाकिस्तान के भीतर जो डर बैठा है, वह केवल हथियारों का डर नहीं है, यह उस नए भारत के आत्मविश्वास का डर है, जो अब किसी उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व दिखाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक विखंडन और आंतरिक चरमपंथ से जूझ रहा देश है। उसकी सेना, जो दशकों तक भारत-विरोधी राष्ट्रवाद पर टिके रहने की आदी थी, अब जानती है कि भारतीय जवाब केवल सीमित नहीं रहेगा। भारत के पास आज राफेल स्क्वाड्रन, सुखोई-30स्न्द्व बेड़े, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, पिनाका रॉकेट सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध तकनीक जैसी क्षमताएँ हैं, जिनका सामना पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान की 'घबराहट' दरअसल एक मनोवैज्ञानिक पराजय है। यह वही डर है जो 1971 में महसूस हुआ था और अब वह डर फिर से कराची और रावलपिंडी की गलियों में लौट आया है।

देखा जाये तो भारत अब उस युग में नहीं है जब 'संयम' को कमजोरी समझा जाता था। 'त्रिशूल' अभ्यास यह संकेत देता है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।

'जेएंडके को छोड़कर भारत में 2013 के बाद नहीं हुआ कोई बड़ा आतंकी हमला', देश की सुरक्षा स्थिति पर गरजे एनएसए

नई दिल्ली,01 नवंबर (एजेंसी)। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में देश की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2013 के बाद से जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में आतंकी हमला नहीं हुआ है। अजीत डोभाल ने कहा कि तथ्य स्पष्ट हैं और इन पर कोई विवाद नहीं हो सकता। भारत ने आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया है। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2005 को देश में एक बड़ी आतंकी घटना हुई थी और उसके बाद 2013 में आखिरी बार देश के अंदरूनी क्षेत्रों में आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरा देश आतंकवादी हमलों से सुरक्षित रहा है।

एनएसए ने बताया कि भले ही दुश्मन ताकतें सक्रिय रहीं, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता के कारण देश के भीतरी हिस्सों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 2014 के बाद से वामपंथी उग्रवाद में भारी कमी आई है। डोभाल ने कहा, 2014 की तुलना में वामपंथी उग्रवाद अब 11 प्रतिशत से भी कम क्षेत्रों में सिमट गया है। जिन जिलों को पहले उग्रवाद प्रभावित घोषित किया गया था, उनमें से अधिकांश को अब सुरक्षित घोषित किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम हो गया है। 'सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमने सुरक्षा उपाय किए हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि हर भारतीय खुद को आंतरिक और बाहरी दोनों ही खतरों से सुरक्षित महसूस करे,' डोभाल ने कहा।

एनएसए ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, 'वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों की देखभाल और उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक है। आधुनिक शासन में महिलाओं को सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण की भावना देना सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।'

पैन-इंडिया साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, आरबीएल बैंक अधिकारी समेत 5 गिरफ्तार

नई दिल्ली ,01 नवंबर (एजेंसी)। अपराध शाखा की साइबर सेल ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह देश में फैले नेटवर्क के जरिए नागरिकों से ठगी कर रहा था। इस गिरोह का संचालन दुबई में बैठे एक भारतीय हैंडलर टॉम के इशारे पर किया जा रहा था। साइबर सेल की कार्रवाई में आरबीएल बैंक के एक अधिकारी सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर और जाली खातों के जरिए ठगी की रकम को इधर-उधर ट्रांसफर करने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मंजीत सिंह (28), मनश्वी (23), मनीष मेहरा (33), सोमबीर (43) और अनुप (35) शामिल हैं।

अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र, फैन्स की बढ़ी चिंता

मुंबई,01 नवंबर (एजेंसी)। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। वैसे तो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र का ये रूटीन चेकअप है, जिसके लिए वो भर्ती हुए हैं, लेकिन फैन्स को उनकी सेहत की चिंता हो रही है।

धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आग की तरह फैली है। ऑनलाइन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सीरियस हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। करीबी परिवार के सूत्र के हवाले से पता लगा है कि कुछ भी सीरियस नहीं है। धर्मेंद्र को उम्र से जुड़ी चीजों को लेकर रूटीन चेकअप के लिए एडमिट किया गया है। धर्मेंद्र की टीम का कहना है कि एक्टर को रेगुलर चेकअप के लिए एडमिट किया गया है। उम्र के चलते उन्हें अपना चेकअप समय-समय पर करवाना पड़ता है। इसलिए वो अस्पताल में हैं। कुछ हफ्ते पहले भी धर्मेंद्र को अस्पताल में देखा गया था। तब भी वो रूटीन चेकअप के लिए ही गए थे। वो पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो धर्मेंद्र ने करण जौहर की फिल्म 'रॉकी रानी की प्रेम कहानी' से सालों बाद कमबैक किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने किसिंग सीन भी दिया था, जिसे देखकर फैन्स के होश उड़ गए थे। धर्मेंद्र जल्द ही श्रीराम राघवन की डायरेक्शन में बनी फिल्म 'इक्कीस' में दिखने वाले हैं। जिसमें एक्टर अगस्त्य नंदा के दादा का किरदार निभाने वाले हैं। जो कि अरुण खेत्रपाल की कहानी पर बेस्ड है। साल 1971 के भारत-पाक युद्ध में अरुण खेत्रपाल को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 15 आधुनिक पिस्तौल बरामद

अमृतसर ,01 नवंबर (एजेंसी)। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 7 आरोपियों पर कार्रवाई की, जिनमें शमशेर सिंह उर्फ सीमा, अमनदीप सिंह उर्फ बॉबी, बलविंदर सिंह उर्फ काका, गुरदेव सिंह, करणप्रीत सिंह, हरमन सिंह और एक नाबालिग शामिल हैं। सभी अमृतसर के निवासी हैं।

रेलवे स्टेशनों पर अब ब्रश करना, बर्तन धोना और थूकना पड़ेगा महंगा, यात्रियों पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली,01 नवंबर (एजेंसी)। अगर आप ट्रेन यात्रा के दौरान प्लेटफॉर्म पर लगे नल से ब्रश करते हैं या खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। रेलवे ने ऐसे यात्रियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रेल अधिनियम 1989 के तहत स्टेशन परिसर में तय स्थानों को छोड़कर अन्य जगह ब्रश करना, थूकना, कपड़े या बर्तन धोना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में यात्रियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों पर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय और वॉशरूम जैसे विशेष स्थान तय किए गए हैं। उन्होंने कहा, प्लेटफॉर्म पर लगे नलों या खुले स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्य करना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि अन्य यात्रियों के लिए असुविधाजनक भी है।

शुक्ला ने बताया कि वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जा रहे हैं और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जल्द ही सभी स्टेशनों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे यात्रियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित शौचालयों और वॉश बेसिन का ही उपयोग करें। साथ ही चिप्स के रैपर, बोतलें या अन्य कचरा ट्रेन या स्टेशन पर न फेंकें। रेलवे ने कहा है कि स्वच्छता बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है, नियम तोड़ने पर जुर्माना और यात्रा में परेशानी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

फलोदी में ट्रक ने टैक्सी को मारी टक्कर, चार लोगों की मौत, 11 घायल

फलोदी,01 नवंबर (एजेंसी)। राजस्थान में फलौदी जिले में शुक्रवार देर रात फलोदी-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर ट्रक की टक्कर से एक टैक्सी में सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि कपास तोड़ने वाले श्रमिक लोडिंग टैक्सी से देर रात बीकानेर मार्ग से जा रहे थे। इसमें महिलाओं बच्चों सहित कुल 15 लोग सवार थे। भादू भाई होटल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने टैक्सी को टक्कर मार दी। इससे टैक्सी में सवार चार लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि वहां होटल में मौजूद लोगों और पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद सात को जोधपुर भेज दिया गया जबकि चार को छुट्टी दे दी गयी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे के शिकार मध्यप्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो हर वर्ष कपास के सीजन में फलोदी क्षेत्र में मजदूरी करने आते हैं।

राहुल गांधी ने आत्महत्या करने वाली महिला डॉक्टर के स्वजन से की बात

मुंबई, 01 नवंबर [एजेंसी]। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सातारा जिले में आत्महत्या करने वाली महिला चिकित्सक के स्वजन से बुधवार को फोन पर बात की।उन्होंने न्याय की उनकी लड़ाई में उन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। महिला चिकित्सक के परिवार के सदस्यों ने न्याय की मांग करते हुए राहुल गांधी से मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कराने के लिए सरकार पर दबाव डालने की मांग की। उन्होंने कहा कि चिकित्सक की मौत हुए एक सप्ताह हो गया है। उन्हें डर है कि सुबूत मिटा दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के फोन से महिला के माता-पिता और भाई-बहनों से बात की। सपकाल बीड जिले के कवड़गांव गांव में उनसे मिलने गए थे।राहल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह महिला चिकित्सक की मौत के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे।

रायपुर में साड़ी बेचने के बहाने कर रहे थे नशे की तस्करी, 70 किलो गांजा के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

रायपुर, 01 नवंबर [एजेंसी]। राजधानी में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और डीडी नगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 70 किलो गांजा के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं, जो महाराष्ट्र और ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, आरोपी एक माह पहले साड़ी बेचने के बहाने रायपुर पहुंचे थे। यहां किराए के मकान में ठहरकर ये लोग साड़ी बिक्री की आड़ में गांजा की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कार में घूम-घूम कर गांजे की डिलीवरी की जा रही है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा और तलाशी में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से रायपुर और आसपास के इलाकों में नशे का कारोबार कर रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह गिरोह अंतरराज्यीय स्तर पर नशे की तस्करी में सक्रिय था।

आरएसएस के कार्यक्रम में लिया था भाग, कर्नाटक में चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

बिदर, 01 नवंबर [एजेंसी]। कर्नाटक स्कूल शिक्षा विभाग ने यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन में भाग लेने वाले चार शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। बिदर जिले के औराद के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मंगलवार को नोटिस जारी किए। अपने नोटिस में बीईओ ने कहा, यह पाया गया है कि आपने सात अक्टूबर, 2025 और 13 अक्टूबर, 2025 को बिदर जिले के औराद (बी) तालुक में आयोजित संघ पथ संचलन में भाग लिया। इस संबंध में वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गई हैं। नोटिस में कहा गया, चूंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपको किसी भी राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। संघ पथ संचलन में भाग लेकर आपने सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन किया है। बीईओ ने उन्हें इस नोटिस को प्राप्त करने के तुरंत बाद एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा। दलित सेना और बहुजन सेवा समिति के नेताओं ने शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई।

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की सरेआम हत्या, सड़क पर 20 मिनट तक पीटा, फिर सीने में मारी गोली

लुधियाना। पंजाब के लुधियाना ज़िले के जगराओं में दिनदहाड़े कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह (23) की हत्या कर दी गई। घटना एसएसपी ऑफिस से महज 250 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर दो कारों में सवार होकर आए थे, जबकि तेजपाल अपनी कार में अकेला था।

सूत्रों के मुताबिक, सड़क पर दोनों कारों की हल्की टक्कर होने के बाद विवाद शुरू हुआ। इसी बीच दोनों गाड़ियों से 7-8 युवक उतरे और तेजपाल पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने करीब 20 मिनट तक बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद जाते-जाते एक आरोपी ने पिस्टल निकालकर उसके सीने में गोली मार दी और सभी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में खिलाड़ी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तेजपाल सिंह, निवासी गिद्दड़विंडी गांव के रूप में हुई है।

घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी और थाना सिटी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि दोपहर लगभग 2:50 बजे हरि सिंह रोड पर तेजपाल और हनी ओमी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें तेजपाल को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। आरोपी हनी ओमी और काला ओमी, दोनों रोमी गांव के रहने वाले हैं।

सीजीपीएससी घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से चार आरोपियों को मिली राहत

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। रायपुर जेल में बंद पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के बेटे नितेश सोनवानी, भतीजे साहिल सोनवानी, कारोबारी श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। चोरों आरोपी पिछले कुछ महीनों से न्यायिक हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत मंजूर की है। इन पर सीजीपीएससी परीक्षा घोटाले के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। सीजीपीएससी घोटाला मामले में सीबीआई ने 30 सितंबर को स्पेशल कोर्ट में 2000 पन्नों का पहला पूरक चालान पेश किया था। इस चालान में घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए थे। एजेंसी ने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। इसके अलावा आरती वासनिक, जीवन किशोर ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आडिल को भी आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों की भूमिका का विस्तार से जिक्र करते हुए सीबीइआई ने सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट को जानकारी दी है। फ्लिहाल सभी आरोपी सीबीआई की न्यायिक रिमांड में जेल में बंद हैं। मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है।

भारतमाला मुआवजा राशि घोटाला: एक महिला सहित तीन पटवारियों को एसीबी ने किया गिरफ्तार

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। भारतमाला परियोजना रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरीडोर के भू-अर्जन प्रकरण में मुआवजा घोटाले में शामिल एक महिला सहित तीन पटवारियों को एसीबी-ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है. तीनों पटवारियों दिनेश पटेल (तत्कालीन पटवारी नायकबांधा), लेखराम देवांगन (तत्कालीन पटवारी टोकरो) व बसंती घृतलहरे (तत्कालीन पटवारी भेलवाडीह) पर आरोप है कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच शासन द्वारा अर्जित भूमि को पुन: शासन को विक्रय कर मुआवजा देने, बैक डेट में बंटवारा और नामांतरण करना, भूमि स्वामी के बदले किसी अन्य को मुआवजा देने एवं निजी भूमि के गलत मुआवजा तथा उसके टुकड़े कर उपखण्डों में विभाजित कर मुआवजा राशि हड़प कर शासन के साथ छल करते हुए धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई. से रोक हटाने जाने के पश्चात् इन्हें गिरफ्तार किया गया है.

चैतन्य बघेल की रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ी

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 12 नवंबर तक बढ़ गई है। चैतन्य बघेल अब 12 नवंबर तक जेल में ही रहेंगे। बता दें कि रिमांड खत्म होने के बाद आज बुधवार को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया और चैतन्य बघेल को 12 नवंबर तक न्यायिक रिमांड में जेल में रहने का आदेश सुनाया। यह भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया। आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे।

दलाल के चंगुल से छूटे 18 मजदूर

बीजापुर, 01 नवंबर (एजेंसी)। ज्यादा मजदूरी और अच्छे काम का लालच देकर जिले के दो ग्राम पंचायतों — कड़ेनार से 11 और घुमरा से 7 — कुल 18 ग्रामीणों को एक दलाल सीनू श्रीनिवास अगस्त माह में तेलंगाना राज्य ले गया था। ग्रामीणों को यह व्यक्ति मजदूरी दिलाने के बहाने बाहर लेकर गया, लेकिन बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की गई। मिली जानकारी के अनुसार, श्रमिक मनोज ताती ने बताया कि पहले इन मजदूरों को तेलंगाना के करीमनगर में काम कराया गया, फिर दलाल द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ भेज दिया गया। इसके बाद वही दलाल सीनू श्रीनिवास ने सभी मजदूरों को कर्नाटक राज्य के जिला बागलकोट अंतर्गत बिगड़ी गांव जानमट्टी में एक साहूकार के यहां ?5 लाख में काम पर लगा दिया। लेकिन मजदूरों को मेहनताना नहीं दिया गया और दलाल फरार हो गया।

टीएस सिंहदेव के टॉकीज में तालाबंदी, 33 साल बाद कलेक्टर पर जुर्माना, निरस्त हुआ था लाइसेंस

अंबिकापुर,01 नवंबर(एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में सरगुजा राजपरिवार के स्वामित्व वाले अलखनंदा टॉकीज का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त करने के 33 साल पुराने बहुचर्चित मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी माना है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि छतवाल राजपरिवार को ब्याज सहित 34,795 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें।यह मामला वर्ष 1992 का है, जब टीएस सिंहदेव द्वारा संचालित अलकनंदा टॉकीज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। लाइसेंस निरस्ती की यह कार्रवाई उस राजनीतिक हलचल के बीच हुई थी, जब वाड्रफनगर के बिजाकुरा गांव में विशेष पिछड़ी जनजाति के रिबई पंडो और उसके परिवार के दो अन्य बच्चों की भूख से मौत की घटना ने तूल पकड़ा हुआ था।राजपरिवार की सदस्य टीएस सिंहदेव की मां पूर्व मंत्री कांग्रेस नेत्री देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ने मामले को लेकर तत्कालीन कलेक्टर के निलंबन की मांग की थी। आदिवासी परिवार की भूख से मौत के मामले ने इतना तूल पकड़ा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को अप्रैल 1992 में स्वयं वाड्रफनगर आकर स्थिति का जायजा लेना पड़ा था।सरगुजा राजपरिवार के अरुणेश्वर शरण सिंहदेव के भाई

की स्वामित्व वाली अलकनंदा टाकीज को नियमानुसार दो मार्च को सिनेमा संचालन का लाइसेंस जारी किया गया था।

टाकीज का संचालन उनके बड़े भाई टीएस सिंहदेव कर रहे थे। इसी दौरान आदिवासी परिवार की भूख से मौत की घटना ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। मुद्दे को पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव ने उठाया था। उस समय प्रदेश में भाजपा के सुंदरलाल पटवा की सरकार थी। बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच 19 अप्रैल 1992 को तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल ने अलकनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देने की अंतिम तिथि 23 अप्रैल थी, लेकिन 24 अप्रैल को जबलपुर हाई कोर्ट ने सिंहदेव परिवार के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर दिया।

सिंहदेव के अधिवक्ता ने उसी दिन शपथपत्र सहित यह आदेश कलेक्टर को देने की कोशिश की परंतु कलेक्टर ने मिलने से इन्कार कर 24 अप्रैल की दोपहर अलकनंदा टाकीज का लाइसेंस निरस्त कर टाकीज का संचालन रोक दिया और 24 एवं 25 अप्रैल के चार शो नहीं चल सके। सिंहदेव ने आठ हजार रुपये की क्षति की जानकारी देते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की। न्यायालय में आबकारी आयुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय में अलकनंदा टाकीज के लाइसेंस निरस्तीकरण से संबंधित कोई फाइल उपलब्ध नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी पाते हुए ब्याज सहित 34,795 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि राजपरिवार को देने का आदेश दिया। यह राशि न्यायालय में जमा करा दी गई है।

पोर्टल में गड़बड़ी ने बढ़ाई परेशानी, छत्तीसगढ़ के 7 लाख से अधिक किसान धान बेचने से हो सकते हैं वंचित

0 प्रदेश भर में 7 लाख 88 हजार 66 किसान ऐसे हैं, जिनका खसरा एकीकृत किसान पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल से मेल नहीं खा रहा

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं, एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन की मियाद भी दो दिन बाद खत्म हो रही है, लेकिन पोर्टल की तकनीकी खामियों के चलते कई किसान पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। छत्तीसगढ़ में 7 लाख से %यादा ऐसे पंजीकृत किसान हैं, जिनका खसरा न तो एग्री स्टेक पोर्टल से मेल खा रहा है और न ही एकीकृत किसान पोर्टल से मेल खा रहा. ऐसे में लाखों किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं।

सरगुजा में 60 हजार किसान होंगे वंचितछत्तीसगढ़ रा%य को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस साल डिजिटल माध्यम से धान फसल की गिरदावरी किए जाने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हजारों ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में धान की फसल लगाई हुई है, लेकिन गिरदावरी में उन खेतों में धान की फसल दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में सरगुजा संभाग के करीब 60 हजार से अधिक किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि किसानों ने इसके लिए आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उन आवेदनों पर भी समय रहते सुनवाई नहीं हो पा रही है।प्रदेश भर में 7 लाख से अधिक किसान हो सकते हैं वंचितइस मामले में अब तक सामने आए पंजीयन के आंकड़े हैरान करने वाले हैं. प्रदेश भर में 7 लाख 88 हजार 66 किसान ऐसे हैं, जिनका खसरा एकीकृत किसान पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल से मेल नहीं खा रहा है।अब सवाल यह है कि लाखों की संख्या में अगर किसान धान नहीं बेच पाएंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या फिर सरकार इसके लिए कोई दूसरा विकल्प निकालेगी? इन हालातों के कारण किसान मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे है। उम्मीद है कि सरकार इसे गंभीरता से लेगी और खामियों को समय रहते दूर करेगी या फिर पंजीयन की समय-सीमा बढ़ाई जाएगी।

छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड ई-केवाईसी का समय खत्म, 20 प्रतिशत लोगों ने नहीं कराया सत्यापन

0 कट जाएगा लिस्ट से इनका नाम

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश में राशन कार्ड सत्यापन की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसके बाद भी अभी 20 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है।

खाद्य संचालनालय की ओर से सभी लोगों को 25 अक्टूबर तक सत्यापन करने के लिए कहा गया था, लेकिन केवल रायपुर जिले में ही करीब 20 फीसदी लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे में अब इन लोगों का नाम राशन कार्ड के हितग्राहियों की लिस्ट से हट सकता है।

4 लाख से अधिक लोगों का सत्यापन बाकी

रायपुर जिले में कुल 6 लाख 48 हजार 464 राशन कार्ड रजिस्टर्ड हैं। इन राशन कार्ड धारकों में 22 लाख 26 हजार 521 सदस्य पंजीकृत हैं। खाद्य विभाग के मुताबिक पंजीकृत सदस्यों में से करीब 18 लाख 7 हजार 52 लोगों ने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। वहीं, 4 लाख 19 हजार 469 पंजीकृत सदस्यों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।

ई-केवाईसी नहीं तो कट सकता सूची से नाम

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बार-बार की सूचना के बावजूद ये लोग राशन दुकानों में जाकर बायोमैट्रिक निशान नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य विभाग, ई-केवाईसी ना कराने वाले लोगों से सख्ती अपनाएगी। जिन लोगों का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है उनका नाम ऑनलाइन सूची से काटा जाएगा।जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 25 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया था। खाद्य संचालनालय से अभी तारीख बढ़ाने को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। तारीख बढ़ती है तो राज्योत्सव के बाद ऐसे कार्डों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी।

डबल इंजन की सरकार में संवर रहा है छत्तीसगढ़

रायपुर,01 नवंबर (एजेंसी)। विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को मुर्त रूप दिया है। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि, महतारी वंदन योजना तथा आवास योजना को सफल बनाने का सपना साकार किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत पीएम आवास योजना को साकार करने के लिए जमीनी स्तर पर जानकारी ली तथा कई दोषी अधिकारियों को दण्डित किया है। गत दिनों केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ा दिया है, जिसके तहत 26 लाख परिवार का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। किसानों को समर्थन मूल्य पर धान की राशि दी जाती है, लेकिन बोनस के रूप में किसान सम्मान निधि के लिए 10 करोड़ रूपए दिया गया है।

प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में डबल इंजन की सरकार आते ही विकास कार्य चौतरफा हो रहे हैं। केन्द्र में मोदी सरकार आते ही राज्य के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। 47,000 करोड़ की लागत से रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन के तहत 40 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल, पीएम आवास योजना से 26 लाख परिवारों का पक्के घर का सपना साकार, पीएम जनमन योजना से 59 हजार परिवारों को मिल रहा लाभ, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान से 6,691 ग्राम लाभान्वित हुए, 40,000 करोड़ से अधिक की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, महतारी वंदन योजना से 69 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में पहुँचे 12,376 करोड़ रूपए, पीएम किसान सम्मान निधि से 25.47 लाख किसानों के खातों में पहुँचे 9,765 करोड़ रूपए पहुंचाए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास हो रहा है।

जवानों की भुजाओं की ताकत से बस्तर लाल आतंक से होगा मुक्त - उपमुख्यमंत्री शर्मा

रायपुर, 01 नवंबर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4 थीं वाहिनी में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री शर्मा ने सभी को एकता दिवस की शपथ भी दिलाई एवं मार्च पास्ट का अवलोकन करने के साथ परेड की सलामी ली।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान अतुलनीय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधते हुए अखंड भारत को मूर्त रूप दिया, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हुआ। बिखरे भारत में राजनैतिक एकीकरण में साहसिक भूमिका निभाने के लिये पटेल को लौह पुरूष कहा जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, यहां के लोगों के बीच एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब देश कई रियासतों में विभाजित था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे एकजुट किया। राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने के लिए इनके संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है।

आजादी के वर्षों बाद भी देश के कुछ भागों में हमारे सुरक्षाबलों के जवान आतंकवाद एवं नक्सलवाद का सामना करते हुए देश की एकता-अखण्डता एवं प्रदेश तथा देशवासियों की सुरक्षा हेतु अदम्य साहस, वीरता एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भी लगभग चार दशकों से नक्सलवाद के दंश को झेलता आ रहा है। छत्तीसगढ़ में कार्यरत छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों एवं केन्द्रीय सुरक्षा बल के सैंकड़ों जवानों ने इस लाल आतंक को समाप्त करने अपने प्राणों की परवाह किये बिना लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्रहित में उनका यह बलिदान सदैव देश और राज्य के स्मृति में अमर रहेगा।

वर्तमान में हम नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के राह में चल पड़े हैं विगत दो वर्षों में जवानों ने जो अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है, उसकी चर्चा और परिणाम हम सब देख पा रहे है, अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि जवानों की भुजाओं की ताकत से बस्तर पूर्ण रूप से लाल आतंक से मुक्त होगा एवं बस्तर के कोने-कोने में लोकतंत्र और संविधान लागू होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड प्राप्त हुआ है, वह हमारे वीर जवानों के पराक्रम एवं गौरव का परिणाम है, जिससे राज्य का मान एवं पुलिस जवानों का आत्म विश्वास बढ़ा है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस अवसर पर नक्सली घटनाओं में शहीद हुए लोगों की याद में लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जहां अब तक हुए नक्सली हमलों में शहीद हुए जवानों के छायाचित्रों को देखकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रदर्शनी में पुलिस की नक्सल ऑपरेशन्स में कार्यप्रणाली एवं कल्याणकारी कार्यों को भी प्रदर्शित किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 4 थीं वाहिनी द्वारा लगाए गए राज्य स्तरीय शस्त्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। जिसमें एलएमजी, यूबीएलजी, असाल्ट रायफल, एसएलआर, जेवीपीसी, एके 47, टियर गन, एक्शन गन आदि का प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान उन्होंने भारत में निर्मित हथियारों पर उत्साह प्रदर्शित किया और अधिकारियों से चर्चा में कहा कि भारत में निर्मित ये अत्याधुनिक हथियार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम हैं ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे बढ़ते कदम हैं। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा एवं श्री अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक श्री अंकित गर्ग, श्री ध्रुव गुप्ता, श्री बीएस ध्रुव, पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री अरविंद कुजूर, श्री सदानंद कुमार सहित पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे एवं शहीदों के परिवारजन उपस्थित रहे।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.- 08102025-266782
CG-CG-E- 08102025-266782
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4443] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947
No. 4443] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना
बिलासपुर 3 अक्तूबर 2025
रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4571 (अ)— रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विषय रेल परियोजना अर्थात "बिलासपुर डिवीजन एमडब्ल्यूआरएन-एसआरबीए के बीच नियंत्रण रेखा -संख्या सीजी 12 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण। (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा) परियोजना (कोरबा) के, छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा, ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, कोरबा छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अन अनुज्ञात कर सकेगा, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन-विशेष रेल परियोजना, अर्थात, "बिलासपुर डिवीजन एमडब्ल्यूआरएन एसआरबीए के बीच- नियंत्रण रेखा संख्या सीजी 12 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण। बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा)।"
(कोरबा जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

जिला का नाम : कोरबा

तहसील का नाम : बरपाली

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित रकबा (हे.)
1	पुरैना	1	1606/1	0.020	0.020
		2	1606/3	0.004	0.004
		3	1606/4	0.016	0.016
		4	1606/5	0.020	0.020
		5	1607/3	0.006	0.006
		6	1695/1	0.121	0.035
		7	1607/30	0.008	0.008
		8	1607/31	0.004	0.004
		9	1607/32	0.006	0.006
		10	1607/33	0.005	0.005
		11	1607/34	0.004	0.004
		12	1678/1	0.198	0.039
		13	1679/1	0.121	0.040
		14	1680/1/क/1	0.065	0.065
		15	1696/9	0.016	0.016
		16	1696/10	0.036	0.036
		17	1680/1/घ	0.045	0.045
		18	1680/1/ग	0.077	0.077
		19	1696/1	0.036	0.036
		20	1696/8	0.041	0.041
		21	1680/1/ख	0.059	0.059
		22	1696/7	0.041	0.041
		23	1696/4	0.036	0.036
		24	1680/3	0.024	0.024
		25	1681/1	0.117	0.060
		26	1681/2	0.117	0.040
		27	1681/3	0.113	0.040
		28	1695/4	0.113	0.047
		29	1696/3	0.016	0.016
		30	1696/5	0.040	0.040
		31	1696/6	0.040	0.040
		32	1606/2	0.012	0.002
		33	1607/17	0.049	0.008
		34	1680/1/क/2	0.004	0.001
		35	1680/4	0.010	0.004
		36	1696/11	0.004	0.001
		37	1696/12	0.004	0.001
		38	1696/15	0.004	0.001
		39	1696/16	0.004	0.001
		40	1696/17	0.004	0.001
			कुल		0.986

कुल भूमि (पुरैना) 0.986 हे.

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/ बी एस पी/आर ओ बी/ एल सी संख्या CG-12/ भूमि अधिग्रहण/12]

सीपीआर/10/413 संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

जिंदगी के मुश्किल दौर को अपनों के दम पर पार कर गई जेमिमा: उनके बयान की 10 मुख्य बातें जो आपको करेंगी प्रेरित

- जेमिमा रॉड्रिग्स की कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की नहीं है...यह हिम्मत, भावनाओं और इंसानियत की कहानी है।
- उनका संदेश साफ है 'मदद मांगना ठीक है और मुश्किल वक्त सिर्फ यह साबित करने आता है कि आप कितने मजबूत हैं।'

मुंबई ,01 नवंबर (एजेंसी)। जेमिमा की कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की नहीं है...यह हिम्मत, भावनाओं और इंसानियत की कहानी है। उनका संदेश साफ है 'मदद मांगना ठीक है और मुश्किल वक्त सिर्फ यह साबित करने आता है कि आप कितने मजबूत हैं।' जेमिमा रॉड्रिग्स ने खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अपनी नाबाद 127 रनों की मैच जिताऊ पारी से पहले उन्होंने मानसिक संघर्ष का एक कठिन दौर झेला था। उन्होंने बताया कि उस समय वह भारी चिंता से गुजर रही थीं, जिससे वह खुद को सुन्न महसूस करती थीं और कई बार रो पड़ती थीं।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेमिमा भावुक हो गईं और कहा कि वह अपनी यह कहानी इसलिए साझा कर रही हैं ताकि उन लोगों की मदद कर सकें जो इसी तरह के मानसिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। जेमिमा की कहानी सिर्फ रन और रिकॉर्ड्स की नहीं है...यह हिम्मत, भावनाओं और इंसानियत की कहानी है। उनका संदेश साफ है 'मदद मांगना ठीक है और मुश्किल वक्त सिर्फ यह साबित करने आता है कि आप कितने मजबूत हैं।' उनके बयान की ये 10 बातें किसी के लिए भी प्रेरणा हैं... जेमिमा के आंसुओं में छिपी जीत की कहानी

जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में नाबाद 127 रनों की पारी खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचाया, लेकिन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आंसू यह बता रहे थे कि इस जीत के पीछे कितनी मानसिक जंग छिपी थी। उन्होंने खुद खुलकर कहा, 'इस टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अगर कोई मुझे देख रहा है और जो इसी दौर से गुजर रहा है, तो उसे पता चले कि मदद मांगना ठीक है।' चिंता और डर से भरे दिनजेमिमा ने बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत ज्यादा उत्कंठा से जूझ रही थी। कई बार मैच से पहले अपनी मां को कॉल करती और सिर्फ रोती रहती थी।' जेमिमा ने बताया कि सब कुछ सुन्न लग रहा था, जैसे शरीर चल रहा हो, लेकिन मन कहीं खो गया हो। उन्होंने कहा, 'ऐसी स्थिति में आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं और खुद में ही रहने की कोशिश करते हैं।' परिवार बना सबसे बड़ा सहाराउन्होंने बताया कि उनके माता-पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहे। जेमिमा ने कहा, 'मेरे मम्मी-पापा ने मुझे संभाला। हर बार कहा- बेटा, तू खुद पर भरोसा रख। यह दौर भी बीत जाएगा।' यही भरोसा उन्हें बार-बार मैदान में लौटने की हिम्मत देता रहा। उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी।'

साथी खिलाड़ियों की भावनात्मक मददजेमिमा ने बताया कि टीम की साथी खिलाड़ी अरुंधति रेड्डी, स्मृति मंधाना, और राधा यादव ने इस मुश्किल दौर में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया, 'अरुंधति के सामने मैं हर दिन रोती थी। मजाक में कहा करती थी- तुम मेरे सामने मत आओ, मैं फिर से रो पड़ूंगी, लेकिन उसने मुझे हर दिन संभाला।' स्मृति मंधाना का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, 'वो मेरे नेट सेशन में बस खड़ी रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। बस उसका होना मेरे लिए बहुत मायने रखता था।' जेमिमा ने कहा, 'राधा हमेशा मेरे साथ रहीं और मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं परिवार कह सकती हूं और मुझे अकेले इस मुश्किल दौर से नहीं गुजरना पड़ा। और मदद मांगना भी ठीक है।'

नौ भारतीय खिलाड़ी नहीं पार कर पाए दहाई का आंकड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने 40 गेंद शेष रहते जीता दूसरा टी20

मेलबर्न , 01 नवंबर [एजेंसी]। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 68 रन की पारी खेली। वहीं, हर्षित राणा ने 33 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ नहीं छू सका।ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 में भारत को चार विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 126 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 13.2 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कंगारुओं ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। अब तीसरा टी20 दो नवंबर को

खेला जाएगा। भारत की पारीभारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 68 रन की पारी खेली। वहीं, हर्षित राणा ने 33 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 35 रन बनाए। इसके अलावा कोई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ नहीं छू सका। बाकी के नौ खिलाड़ियों में से चार खिलाड़ी तो खाता भी नहीं खोल सके। इनमें तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। शुभमन गिल पांच रन, संजू सैमसन दो रन और कप्तान सूर्यकुमार एक रन बना सके। इसके अलावा अक्षर पटेल सात रन और शिवम दुबे चार रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने तीन विकेट लिए। वहीं, जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस को दो-दो विकेट मिले। स्टोइनिस ने एक विकेट लिया। ऑस्ट्रेलिया की पारी126 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। इस साझेदारी को वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा। उन्होंने हेड को आउट किया। हेड ने 15 गेंद में तीन चौके और एक छक्के की मदद से 28 रन की पारी खेली। वहीं, मार्श अर्धशतक से चूक गए। वह 26 गेंद में दो चौके और चार छक्कों की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। जोश इंग्लिस ने 20 रन बनाए। वहीं, टिम डेविड एक रन बना सके। बुमराह हैट्रिक से चूके इसके बाद बुमराह का जलवा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई पारी के 13वें ओवर में बुमराह हैट्रिक से चूक गए। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल ओवेन को विकेटकीपर सैमसन के हाथों कैच कराया। वह 14 रन बना सके। इसके बाद पांचवीं गेंद पर मैथ्यू शॉर्ट को बेहतरीन यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड किया।

इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की वजह से हारा भारत! सूर्यकुमार ने किया खुलासा, अभिषेक की तारीफ की

मेलबर्न ,01 नवंबर । ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर आउट हो गई। अभिषेक ने 37 गेंद में 68 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया।ऑस्ट्रेलिया के हाथों दूसरे टी20 मैच में चार विकेट से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुक्रवार को कहा कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी से अपने लिए एक पहचान बनाई है और उसे आगे भी इसी तरह से खेलते रहना चाहिए।

वहीं, भारतीय कप्तान ने हार की वजह जोश हेजलवुड की बेहतरीन गेंदबाजी को बताया है।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम 18.4 ओवर में 125 रन पर आउट हो गई। अभिषेक ने 37 गेंद में 68 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया। सूर्यकुमार ने मैच के बाद कहा, 'अभिषेक काफी समय से ऐसे ही खेल रहा है। उसे अपने खेल और अपनी पहचान के बारे में पता है।'उन्होंने कहा, 'वह इसमें बदलाव नहीं करने जा रहा और उम्मीद है कि वह ऐसे ही खेलता रहेगा और हमारे लिए ऐसी कई पारियां खेलेगा।

' भारतीय कप्तान ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड की तारीफ की जिन्होंने 13 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे। उन्होंने कहा, 'पावरप्ले में जिस तरह से हेजलवुड ने गेंदबाजी की, वह बेहतरीन थी। पावरप्ले में चार विकेट गिरने के बाद दबाव से उबरना मुश्किल है।

व्यापार

चार राज्यों में 15,095 करोड़ की दलहन-तिलहन खरीद को मंजूरी, निवेशकों के लिए सेबी का नया कदम

नई दिल्ली , 01 नवंबर [एजेंसी]। केंद्र सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र समेत चार राज्यों के किसानों से 15,095.83 करोड़ रुपये की दलहन और तिलहन खरीद योजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में योजना को मंजूरी दे दी। इससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। आधिकारिक बयान में कहा गया कि चौहान ने इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां दीं। कृषि मंत्री ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत 38.44 करोड़ से 4,430 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी, जो तेलंगाना में राज्य के कुल उत्पादन का 25% है। उड़द की 100% और सोयाबीन की 25% खरीद होगी।छोटे निवेशकों को डेट प्रतिभूतियों में निवेश करने पर मिलेगा प्रोत्साहनबाजार नियामक सेबी ने खुदरा निवेशकों की कुछ श्रेणियों को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहनों का प्रस्ताव दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इश्यूअर्स को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सशस्त्र बलों के कर्मियों और खुदरा ग्राहकों जैसे निवेशकों को ज्यादा ब्याज दर या निर्गम मूल्य पर छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की मंजूरी देने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव सेबी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के सार्वजनिक निर्गम पर हालिया आंकड़ों के विश्लेषण के बाद आया है। इस तरह के निर्गमों से जुटाई गई राशि 2023-24 के 191.68 अरब से घटकर 2024-25 में 81.49 अरब रुपये रह गई है। वर्तमान में सेबी किसी भी निर्गम से जुड़े व्यक्ति को वैध शुल्क या कमीशन को छोड़कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद, वस्तु या सेवाओं के रूप में प्रोत्साहन देने से रोकता है। उधर, सेबी ने बड़े कर्ज वाली कंपनियों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अब उन सूचीबद्ध कंपनियों को ही बड़ा माना जाएगा, जिनका आकार 5,000 करोड़ रुपये होगा

आंकड़े उड़ा देंगे होश : 10 करोड़ लोगों ने मनाया छठ पर्व, देश में हुआ 50,000 करोड़ रुपये का व्यापार

नई दिल्ली , 01 नवंबर [एजेंसी]। हर वर्ष पूरे देश में विश्वास और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले चार दिवसीय छठ पर्व को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्यापार के आंकड़े जारी किए हैं। कैट की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 10 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा छठ पूजा मनाई गई, जिससे 50 हजार करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ।इसमें से अकेले राजधानी दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ।

क्रेडिट कार्ड खर्च हर महीने 2.20 लाख करोड़ पार, 23 बढ़ा बकाया; अब दैनिक खरीदारी में भी बढ़ा इस्तेमाल

नई दिल्ली , 01 नवंबर [एजेंसी]। भारत में हर महीने क्रेडिट कार्ड से खर्च 2.20 लाख करोड़ पार। वर्ल्डलाइन रिपोर्ट के मुताबिक, 18 महीनों में बकाया 23% बढ़ा। अब लोग दैनिक खरीदारी के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे।देश में क्रेडिट कार्डधारकों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच खर्च में भी तेजी देखी जा रही है। क्रेडिट कार्ड से हर महीने खर्च 2.20 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। खास बात है कि क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च सिर्फ यात्रा और उच्च-मूल्य वाली ई-कॉमर्स खरीदारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोग अब खाने-पीने के सामान, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कम मूल्य वाले उत्पाद खरीदने में भी इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं।

वर्ल्डलाइन की बुधवार को जारी इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी, 2024 से जून, 2025 के बीच यानी 18 महीनों में क्रेडिट कार्ड बकाये में 23 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई?है।?हालांकि, क्रेडिट कार्ड के बढ़ते उपयोग के बाद भी प्रति लेनदेन औसत टिकट साइज में 6 फीसदी की गिरावट आई है।रिपोर्ट के मुताबिक, जून, 2025 तक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन संख्या के लिहाज से 36 फीसदी बढ़कर 1.32 अरब पहुंच गया है।?वहीं, खर्च 17 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 7.02 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। हालांकि, डेबिट कार्ड से होने वाले लेनदेन की संख्या 28 फीसदी घटकर 17.4 करोड़ रह गई?है।?नेटबैंकिंग से 2025 की पहली छमाही में 717.4 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए। यह 2024 की पहली छमाही से 30 फीसदी अधिक है। हालांकि, नेटबैंकिंग लेनदेन की संख्या एक फीसदी घटकर 2.22

अरब रही।औसत लेनदेन का आकार बढ़कर 3,13,954 रुपये पहुंच गया, जो सभी भुगतान माध्यमों में सर्वाधिक है। एक साल पहले की समान अवधि में औसत लेनदेन आकार 2,39,421 रुपये था।आंकड़े बताते हैं कि नेटबैंकिंग अब भी वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ है। कॉरपोरेशन, कोषागार और सरकारी एजेंसियां टैक्स भुगतान, जीएसटी एवं बड़े आकार के लेनदेन के लिए नेटबैंकिंग पर निर्भर हैं।मोबाइल भुगतान में 30 फीसदी का उछाल

2025 की पहली छमाही में मोबाइल से 209.7 लाख करोड़ रुपये के 98.9 अरब लेनदेन हुए। संख्या के लिहाज से लेनदेन में 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, औसत टिकट साइज 10 फीसदी घटकर 2,120 रुपये रह गया। फास्टैग से भुगतान की संख्या सालाना आधार पर 16 फीसदी बढ़कर 2.32 अरब पहुंच गई। मूल्य के लिहाज से भुगतान 18 फीसदी बढ़कर 405 अरब रुपये पहुंच गया।शीर्ष-पांच जारीकर्ता बैंकक्रेडिट कार्ड : एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक।डेबिट कार्ड : एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।यूपीआई : लेनदेन में 35 फीसदी की तेजीरिपोर्ट के मुताबिक, 18 माह में यूपीआई लेनदेन की संख्या में 50.82 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है। जनवरी, 2024 में कुल 12.2 अरब यूपीआई लेनदेन हुए थे, जिनकी संख्या जून, 2025 तक बढ़कर 18.4 अरब पहुंच गई।2025 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में कुल 143.34 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेनदेन हुए, जो सालाना आधार पर 23 फीसदी अधिक है। वहीं, यूपीआई लेनदेन की संख्या 35 फीसदी बढ़कर 106.36 अरब पहुंच गई।हालांकि, यूपीआई लेनदेन का औसत टिकट साइज 2024 की पहली छमाही के 1,478 रुपये से 9 फीसदी घटकर 1,348 रुपये रह गया।टिकट साइज का मतलब हर ग्राहक की ओर से किए औसत भुगतान से है।वर्ल्डलाइन इंडिया के सीईओ रमेश नरसिम्हन ने बताया, औसत टिकट साइज में गिरावट का मतलब कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यूपीआई की शक्ति है। किराना, डिलीवरी प्लेटफॉर्म, मोबिलिटी सेवाओं और यूटिलिटी पर कम खर्च यह दर्शाता है कि क्यूआर कोड डिफॉल्ट भुगतान मोड के रूप में सामान्य हो गए हैं।

अनिल अंबानी की कंपनियों से यस बैंक को 2700 करोड़ का नुकसान, अनमोल अंबानी की भूमिका पर जांच जारी

नई दिल्ली , 01 नवंबर [एजेंसी]। सीबीआई ने खुलासा किया कि अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश से यस बैंक को 2,700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अनमोल अंबानी की भूमिका पर जांच जारी है।

यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की ओर से अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली वित्तीय कंपनियों में निवेश करने के एक तरफा फैसले से बैंक को 2,700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यस बैंक और अनिल अंबानी की कंपनियों के बीच कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़े मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में यह बात कही गई है।सीबीआई ने कहा, अनिल अंबानी के बेटे और रिलायंस कैपिटल के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक अनमोल अंबानी की भूमिका के बारे में आगे की जांच जारी है। यह मामला यस बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की ओर से दर्ज की दो अलग-अलग शिकायतों पर आधारित है। आरोपपत्र के अनुसार, बैंक ने जब राणा कपूर इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, 2017 और 2019 के बीच अनिल धीरूभाई अंबानी (एडीए) समूह की वित्तीय कंपनियों में 5,010 करोड़ रुपये का निवेश किया।

इन निवेशों में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) में 2,965 करोड़ रुपये और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के वाणिज्यिक पत्रों में 2,045 करोड़ रुपये शामिल थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि कुल राशि में से 3,337.5 करोड़ रुपये दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) में बदल गए।

बैंक इन निवेशों के विरुद्ध प्रतिभूतियों से संपूर्ण एनपीआई की वसूली नहीं कर सका और इस प्रकार उसे 2,796.77 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। एडीए की कुछ संस्थाएं मुखौटा कंपनियां पाई गईं।

इथेनॉल उत्पादन के लिए कम उपयोग से बढ़ा चीनी भंडार, सरकार दे सकती है निर्यात की मंजूरी

नई दिल्ली , 01 नवंबर [एजेंसी]। भारत में इथेनॉल उत्पादन घटने से चीनी भंडार बढ़ गया है। सरकार 2025-26 विपणन वर्ष में चीनी निर्यात की मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजय चोपड़ा ने कहा कि शुरुआती स्टॉक पर्याप्त है और निर्णय जल्द लिया जा सकता है।सरकार 2025-26 के विपणन वर्ष में चीनी निर्यात की मंजूरी दे सकती है। इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के कम उपयोग के कारण ज्यादा भंडार हो गया है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा, चीनी मिलों ने 2024-25 में इथेनॉल निर्माण के लिए 34 लाख टन चीनी का उपयोग किया। यह अनुमानित 45 लाख टन से कम है।चोपड़ा ने कहा, अक्तूबर से सितंबर तक चलने वाले 2025-26 विपणन वर्ष के लिए शुरुआती स्टॉक अधिक

है। 2025-26 में चीनी उत्पादन 3.4 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है। सालाना घरेलू मांग 2.85 करोड़ टन है। हमारे पास निश्चित रूप से चीनी का भंडार ज्यादा है। जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि सरकार उद्योग को निर्यात की योजना बनाने के लिए एक लंबा समय देना चाहेगी।इस पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों की एक समिति अगले सप्ताह बैठक कर सकती है। विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान देश से 10 लाख टन के आवंटन के मुकाबले लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया था। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कीमतें रिफाइंड चीनी के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं। रिफाइंड चीनी की वैश्विक कीमत 3,829 रुपये प्रति क्विंटल है। औसत एक्स मिल कीमत 3,885 रुपये प्रति क्विंटल है। चीनी उद्योग ने अक्तूबर में समाप्त होने वाले 2024-25 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष में शीरे से 471 करोड़ लीटर इथेनॉल की आपूर्ति की पेशकश की थी, लेकिन केवल 289 करोड़ लीटर ही आपूर्ति की गई। चोपड़ा ने कहा, शीरे से इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध हटा दिए हैं।

कोरबा से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म बर्थ की दिक्कत नहीं

चांपा-बिलासपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में कन्फर्म टिकट के लिए मशक्कत

कोरबा (छ.ग.गौरव) । दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के बाद भी ट्रेनों में भीड़भाड़ कम नहीं हुई है। कोरबा से लंबी दूरी की जो भी ट्रेनें हैं, उनमें कंफर्म बर्थ की दिक्कत नहीं के बराबर है, लेकिन चांपा-बिलासपुर से गुजरने वाली उत्तर भारत की ट्रेनों में टिकट पाने यहां के यात्रियों को मशक्कत करनी पड़ रही है।

फिलहाल छठ पूजा संपन्न होने के बाद लौटने वालों की वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। एक नवंबर को एकादशी के बाद विवाह वाले परिजनों की यात्रा शुरू हो जाएगी। पहले से रिजर्वेशन नहीं करा पाने वाले लोगों के लिए कंफर्म टिकट प्राप्त करना आसान नहीं रह गया है।उसलापुर से गुजरने वाली दुर्ग छपरा, सारनाथ एक्सप्रेस हो या फिर गोंदिया बरौनी, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस की बात करें या फिर उत्कल एक्सप्रेस, गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ ही दुर्ग जम्मूतवी एक्सप्रेस भी में सफर करने वालों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाएगा। इन ट्रेनों में ऐसे लोग, जिन्हें 15 नवंबर से पहले यात्रा शुरू करनी है, उन्हें ट्रेन के अलावा सड़क मार्ग या फिर अन्य मार्ग से यात्रा करने की मजबूरी है। इन ट्रेनों का उल्लेख हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोरबा के लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। इन यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। जिन यात्रियों को कोरबा- अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सफर करना है या फिर कोरबा- यशवंतपुर वैनगंगा व कोरबा- त्रिवेन्द्रमनार्थ कोच्चुवेली द्वि-साप्ताहिक ट्रेन में, उनके लिए बड़ी राहत है। इन ट्रेनों में 5 दिन बाद भी यात्रा शुरू करनी हो तो अभी से टिकट लेने पर कंफर्म बर्थ मिल जाएगी। संभावना है कि एक सप्ताह बाद यह स्थिति न बन सके। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेस व शिवनाथ एक्सप्रेस में भी एक सप्ताह के बाद यात्रा करने वालों को कंफर्म बर्थ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

हसदेव महाआरती का आयोजन रद्द

भव्य आयोजन के साक्षी बनने से शहरवासी रह जाएंगे वंचित

कोरबा (छ.ग.गौरव) । लगातार खींचतान और विवाद के बाद आखिरकार हिंदू क्रांति सेना ने सर्वमंगला नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाली हसदेव महाआरती के आयोजन को रद्द कर दिया है। पांच नवंबर को यह आयोजन प्रस्तावित था। इसकी भव्य तैयारी की जा रही थी। कार्ड छपकर बांटे जा चुके थे। शहरवासियों को इस दिन प्रत्येक वर्ष इस खास आयोजन का इंतजार रहता है। लेकिन इस दिस अब एक बड़े आयोजन के साक्षी बनने से शहरवासी वंचित रह जाएंगे।

इसकी वजह संगठनों के मध्य आपसी खींचतान है। हिंदू क्रांति सेना ने आयोजन को रद्द कर दिया है। जिसकी जानकारी संगठन के अध्यक्ष राहुल चौधरी ने टीपी नगर स्थित तिलक भवन में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। इस वर्ष प्रशासन ने एक ही घाट को आधा-आधा बांटकर हिंदू क्रांति सेना और नमामि हसदेव समिति दोनों को अनुमति दे दी है। इसके पूर्व के वर्षों में नदी के दोनों तट पर दोनों संगठनों को अनुमति दी जाती थी। जिससे अधिक विवाद पैदा हुआ, इसके बाद ही हिन्दू क्रांति सेना ने इस आयोजन से हाथ खींच लिया है। यह भी कहा है कि भविष्य में यह आयोजन होगा या नहीं होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। हिंदू क्रांति सेना के अध्यक्ष राहुल चौधरी का कहना है कि हर वर्ष हसदेव महाआरती का भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी आयोजन 5 नवंबर को होना था, लेकिन इस आयोजन को विवादों के कारण रद्द कर दिया है। जिस तरह लगातार हसदेव महाआरती के आयोजन में विवाद की स्थिति बनी हुई है।

बहू से छेड़छाड़, पति, ससुर व जेठ को सुनाई गई सजा

कोरबा (छ.ग.गौरव) । घर में बहू से छेड़छाड़ के दोषी जेठ और विरोध करने पर परिवार की इज्जत बदनाम करने के आरोप में महिला से मारपीट के तीन दोषियों को कोरबा की फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। साथ ही जेठ को एक अन्य धारा में एक साल की सजा सुनाया है।

घटना उरगा थाना क्षेत्र की है। इस साल छह मार्च को एक महिला भोजन करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसका पति घूमने के लिए बाहर चला गया था। इस बीच महिला का जेठ कमरे में पहुंचा। जेठ ने दरवाजे को भीतर से बंद कर दिया। महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने लगा। महिला जोर- जोर से शोर मचाने लगी। जेठ दरवाजे को खोलकर बाहर भाग गया। इस बीच आवाज सुनकर महिला का पति और ससुर घर पहुंचे। साथ में जेठ भी आ गया। तीनों ने महिला पर परिवार की इज्जत को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए मारपीट किया। महिला ने घटना की जानकारी अपने करीबी लोगों को दिया। पुलिस को अवगत कराया गया। केस दर्जकर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस ने महिला के पति, उसके जेठ और ससुर पर अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उसकी सुनवाई कोरबा के फॉस्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने महिला के बयान और सबूतों के आधार पर अलग- अलग धाराओं में तीनों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने ससुर और पति को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सज़ा से दंडित किया। दोनों पर जुर्माना लगाया। दोषी जेठ को एक वर्ष की सजा से दंडित करते हुए एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया। जेठ को कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सज़ा से भी दंडित किया है।

दो झुंड में बटे हाथी, फसल को किया चौपट

एक झुंड में 15 दूसरे में 27 हाथी शामिल

कोरबा (छ.ग.गौरव) । कटघोरा वनमंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। यहां के पसान रेंज में 42 हाथी विचरण कर रहे हैं। हाथियों का दल पहले एक साथ चल रहा था, लेकिन बीती रात दो झुंडों में बंट गया और एक झुंड में 15 तथा दूसरे में 27 हाथी शामिल हो गए। 15 की संख्या वाला झुंड तनेरा पहुंच गया है, जबकि 27 हाथी अभी भी सेमरहा बीट के हरदेवा जंगल में है। हाथियों के दल ने दोनों ही स्थानों पर उत्पात मचाते हुए दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों के फसल को नुकसान पहुंचाया है।

हाथियों के द्वारा क्षेत्र में लगातार उत्पात मचाए जाने से जहां ग्रामीण परेशान हैं, वहीं वन अमला भी चिंतित है। ग्रामीणों को अपने फसल को बचाने के लिए हाथियों से जूझना पड़ रहा है, तो वन विभाग इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास में लगा हुआ है। लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है और हाथियों द्वारा क्षेत्र में लगातार उत्पात मचाए जाने के साथ ही फसल रौंदने का सिलसिला जारी है। हाथियों के डर से कई ग्रामीण अपने धान की फसल को पूरी तरह पककर तैयार होने से पहले ही काट रहे हैं और अपने खलिहानों में लाने को मजबूर हैं। इधर कोरबा वनमंडल के करतला रेंज में हाथियों की फिर से दस्तक हो गई है। हाथियों के दल ने यहां फसल रौंदने के बाद अपना लोकेशन बदल दिया है जिससे पता लगाने में वन अमला जुटा हुआ है।

चोरी कराने का आरोप लगाकर बंधक बनाकर मारपीट

कोरबा (छ.ग.गौरव) । टायर की फैक्ट्री में सेल्समैन का काम करने वाले पर चोरी करवाने का इल्जाम लगाकर मारपीट करने और बंधक बनाने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री के मालिक पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

मामले का प्रार्थी इमरान भारती पिता कुद्दुस उम्र 32 वर्ष पता कुंआभट्ठा टायर की खरीदी- बिक्री का काम करता है। पीड़ित ने सिविल लाइन थाना रामपुर में बताया कि अंकुश आग्रवाल का टायर का फैक्ट्री सलोरा में स्थित है, जहां वह टायर की सप्लाई का कार्य करता है।

उसके द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे कॉल करके अंकुश अग्रवाल के द्वारा उस पर टायर चोरी का आरोप लगाया गया। उसके बाद 28 अक्टूबर को रात्रि लगभग 1.30 बजे इमरान के व्हाट्सअप ग्रुप में अंकुश अग्रवाल द्वारा मैसेज किया गया कि मेरे ऑफिस में आओ और अपने आपको सही साबित करो कि टायर चोरी नहीं करवाया है। अंकुश अग्रवाल ने मैसेज कर कहा कि चांद, नसीम, राजा, सब लोग ऑफिस में आओ और अपने आपको सही साबित करो कि टायर चोरी नहीं करवाया है और सब अगर ऑफिस में नहीं आए तो तुम्हारा बचा हुआ पैसा नहीं मिलेगा। इसके पश्चात् आरिफ जो कि टायर का कार्य करता है उसका फोन आया और उसने कहा कि अंकुश कोसाबाड़ी इंडस्ट्रीयिल एरिया वाले ऑफिस में बुला रहे हैं। फिर प्रार्थी अपने भांजा राजा को लेकर कोसाबाड़ी, इंडस्ट्रीयिल एरिया अंकुश अग्रवाल के ऑफिस पहुंचा तो पहुंचते साथ ही अंकुश अग्रवाल और उसके साथ अन्य साथी लोग मारपीट, गाली-गलौच करने लगे और इमरान पर यह आरोप लगाने लगे कि सलोरा फैक्ट्री से टायर की चोरी होती थी, इस बात की जानकारी तुमको थी और तुम लोगों ने उसे नहीं बताया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूँगा, ऐसा कहते हुए लगभग 2 घंटा तक इमरान व भांजा राजा के साथ बंधक बनाकर मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। इस दौरान इमरान के पास रखे हुए 4900 रूपये को भी अंकुश अग्रवाल के साथ मारपीट करने वाले युवक ने इमरान के पॉकिट से अचानक निकाल लिया। जबरन और मारने की धमकी देते हुए मोबाईल में वीडियो बनाकर जबरदस्ती कबूल करवाया कि पिछली जितनी भी चोरी हुई है उसका हर्जाना भरने की धमकी दी गई। इमरान के मुताबिक उसने डरकर बयान दिया। फिलहाल इमरान की रिपोर्ट पर अंकुश अग्रवाल एवं उसके अन्य साथी के विरुद्ध धारा 115(2), 127, 296, 3(5), 304(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

छात्रों को बड़ी सौगात: दुनियाभर के रिसर्च जर्नल्स मुफ्त

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत मिलेगा लाभ

कोरबा (छ.ग.गौरव) । छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अब वैश्विक स्तर के रिसर्च जर्नल्स तक निशुल्क पहुंच मिलेगी। केंद्र सरकार की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल्स, रिसर्च पेपर और ई-लाइब्रेरी संसाधन बिना किसी शुल्क मिलेंगे। यह सुविधा दिसंबर से शुरू होने जा रही है।

अब तक छात्रों को इन जर्नल्स के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। कई कॉलेज महंगे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते थे, जिससे शोध कार्य प्रभावित होता था। अब यह बाधा खत्म हो जाएगी। योजना के तहत प्रदेश के 14 विश्वविद्यालय, 32 इंजीनियरिंग कॉलेज (3 शासकीय, 28 निजी), 380 सामान्य कॉलेज को मुफ्त एक्सेस मिलेगा। इससे 46 हजार तकनीकी छात्र और 9536 शोध स्कॉलर्स सीधे लाभान्वित होंगे। बीटेक और एमटेक छात्रों को उनके प्रोजेक्ट्स और रिसर्च के लिए विश्वस्तरीय सामग्री घर बैठे मिल पाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इसका सबसे अधिक फायदा होगा। विद्यार्थी और शोधार्थी दुनियाभर के प्रकाशकों के 13,000 प्लस ई-जर्नल्स वैज्ञानिक शोध, पेटेंट डेटा, तकनीकी रिसोर्स और संदर्भ सामग्री एक क्लिक में प्राप्त कर सकेंगे। पूरा सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालय इस योजना के दायरे में आ जाएंगे। इन संस्थानों को अब महंगी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं चुकानी पड़ेगी, जिससे बजट पर भी दबाव कम होगा।

142 दिन बाद योग निद्रा से जागे जगत के पालनहार, मांगलिक कार्य शुरू

एकादशी पर गन्ने के मंडप के नीचे हुआ तुलसी विवाह

कोरबा (छ.ग.गौरव) । लगभग साढ़े चार महीने से थमी शहनाईयों की गूंज अब फिर से बजने को तैयार है। 12 जून को गुरु अस्त होने और 6 जुलाई से चातुर्मास लगने से जिन शुभ कार्यों पर विराम लग गया था, वे 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से पुनः प्रारंभ होंगे। 142 दिनों बाद फिर शादी का मौसम गुलजार होगा। देवउठनी एकादशी के साथ ही देवताओं का चातुर्मास समाप्त होगा। इसके साथ ही चार माह से बंद मांगलिक कार्यों की शुरूआत होगी। घरों के आंगन में गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह रचाया गया। शादी-ब्याह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य जो रुके हुए थे, वे चातुर्मास समाप्त होने पर फिर से शुरू हो जाएंगे।

पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की आखिरी एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी तिथि की शुरूआत 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट पर हुई और समापन 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर होगा। ऐसे में 1 नवंबर को देवउठनी व्रत किया गया।देवशयनी एकादशी के बाद से मांगलिक कार्यों पर विराम लगा था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई गई। देवउठनी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी मैया का विवाह का विधान है, इसके लिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है। पर्व के नजदीक आते ही शहर में गन्ने का बाजार गुलजार है। इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तुलसी चौरा के सामने श्रीशालीग्राम की मूर्ति रखकर गन्ने का मंडप बनाया गया। घर की चौखट के चारों ओर दीप जलाकर अमरूद, बनबेर, चनाभाजी, सिंघाड़ा, केला, मूली, बैंगन, सेवफल आदि भगवान को समर्पित कर तुलसी विवाह संपन्न कराया जा रहा है। पर्व के लिए जरूरी गन्ना बाजार में पहुंच चुका है। इस दिन गन्ना की विशेष मांग रहती है। इसी देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था। इस कारण इस दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। नगर में प्रमुख रूप से गन्ना अम्बिकापुर व पंडरिया से आता है। पंडरिया से गन्ने कर आवक तो पिछले चार से पांच वर्ष ही बंद हो गई थी, इस वर्ष अम्बिकापुर से भी गन्ना नहीं आ रहा है। दोनों स्थानों पर शक्कर की मिलें स्थापित हो गई है, इसलिए गन्ना बाहर नहीं बेचा जा रहा है। फिर भी किसी तरह कम मात्रा में वहां का गन्ना पहुंचा है। इस बार गन्ने की लोकल आवक हो रही है।

राज्य स्थापना दिवस पर सौर ऊर्जा से पहाड़ी कोरवाओं के जगमगाए आशियाने

डीएमएफ से विशेष पिछड़ी जनजाति के 330 परिवार के घरों को किया जा रहा है सौर ऊर्जा से रोशन

कोरबा (छ.ग.गौरव) । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी पर जिले के दूरस्थ अंचलों में विकास की नई किरण पहुँची है। ग्रामीण अंचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के घर अब सौर ऊर्जा से जगमगा उठे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सोच और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशानुसार की गई पहल ने इन परिवारों के जीवन में उजियारे के साथ सम्मान का संचार किया है।

यह पहल केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता और विकास के गहरे भावों से जुड़ा प्रयास है। विशेष पिछड़ी जन जाति के परिवारों में अब सौर ऊर्जा ने वहाँ नई उम्मीद, नई प्रेरणा और नई रोशनी जलाई है। राज्य की रजत जयंती पर यह पहल विकास की वास्तविक कहानी बनकर उभर रही है ,एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जन जाति के पूर्ण हुए 330 आवासों में अभी सौर पैनल लगा कर सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जा रही है। शेष पीवीटीजी आवास पूर्ण होने पर उनमें भी सौर ऊर्जा से बिजली सुविधा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना,डीएमएफ मद के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत योजना के अभिसरण मॉडल के रूप में यह कार्य न केवल ऊर्जा उपलब्धता का समाधान है, बल्कि एक सशक्त और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम भी है। इन योजनाओं के अंतर्गत पहाड़ी कोरवा परिवारों को स्थायी आवास के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र भी प्रदान किए गए हैं, जिससे उन्हें 24 घंटे स्वच्छ और नि:शुल्क बिजली मिल सकेगी। इन घरों में अब बच्चे रात में पढ़ पा रहे हैं और परिवारों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सौर ऊर्जा की सुविधा मिलने से अब पीवीटीजी परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिल गई है। पतरापाली निवासी बंधन सिंह कोरवा का कहना है कि बिजली से भी सस्ती और फायदेमंद सौर ऊर्जा से अब हमारे घर रोशन हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं,सौर ऊर्जा सस्ती और सरल है। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भविष्य में इन परिवारों को सौर ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली विक्रय कर आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

आत्मनिर्भरता,सम्मान और नई शुरुआत के प्रतीक

कलेक्टर अजीत वसंत का कहना है कि प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सौर ऊर्जा से रोशन हुए ये घर केवल बिजली के नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता,सम्मान और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि यह पहल कोरबा जिले में विकास और संवेदना का अद्भुत संगम है। राज्योत्सव पर पहाड़ी कोरवा परिवारों के चेहरों पर जो खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा है, वही हमारे प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता है। राज्य स्थापना दिवस और देवउठनी एकादशी के इस अवसर पर कोरबा प्रशासन ने न केवल घरों में उजियारा फैलाया है, बल्कि दिलों में भी उम्मीद की लौ प्रज्वलित की है। यह राज्योत्सव पहाड़ी कोरवा परिवारों के लिए केवल एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन में नए उजाले और नए आरंभ का प्रतीक बन गया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक किशोर शर्मा द्वारा कावेरी प्रिंटर्स, सी-35,प्रेस काम्पलेक्स टी.पी. नगर कोरबा (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित संपादक किशोर शर्मा, पंजीयन क्रमांक 7585/61 फोन नं. 07759-357623